सितंबर 2023
खंड - XXXIX | अंक - III

एक्ज़िमिअस:
निर्यात लाभ

इस अंक में

- भारत के मध्य–निर्यात जिलों का आकलन : ओडीओपी–डीईएच के तहत अवसर
- भारत–कनाडा आर्थिक संबंधों को बढ़ाना का परिप्रेक्ष्य : रुझान और संभावनाएं
- अफ्रीका में भारत की निवेश संबंधी संभावनाएं
- भारत और बांग्लादेश के बीच घनिष्ठ सहयोग के अवसर
- जोखिम, बीमा और कल्याण पर निबंध

इंडिया एक्ज़िम बैंक
की तिमाही प्रकाशन
केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र संकुल,
कफ़ परेड, मुंबई - 400 005.
फोन: 022 2217 2600
ईमेल: ccg@eximbankindia.in
www.eximbankindia.in
www.eximmitra.in

भारत के मध्य–निर्यात जिलों का आकलन : ओडीओपी–डीईएच के तहत अवसर

– **राहुल मजूमदार**, *सहायक महाप्रबंधक*
साक्षी गर्ग, *उप–प्रबंधक*

पीढ़ियों से, भारत के समुदायों ने कृषि, हस्तशिल्प, आभूषण, वस्त्र और अन्य क्षेत्रों में अद्वितीय कौशल एवं विशेषज्ञता विकसित की है। ये कौशल उनकी सांस्कृतिक विरासत के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं और उन्होंने क्षेत्र–विशिष्ट वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला में वृद्धि की है। तो सीमित संख्या में उत्पादों के लिए प्रयासों व संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करके, क्षेत्र विशेषज्ञता और प्रतिस्पर्धी लाभ विकसित किए जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई भारत की "एक जिला एक उत्पाद" (ओडीओपी) पहल का उद्देश्य प्रत्येक जिले की अनूठी विशेषज्ञता का लाभ उठाकर क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। बाद में, भारत सरकार ने भी ओडीओपी पहल को अपनाया। मार्च 2023 तक, भारत के 766 जिलों में से, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा कार्यान्वित केंद्रीय प्रयोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण (पीएमएफएमई) योजना" के तहत 35 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 713 जिलों के लिए ओडीओपी को स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2022 में, जिलों को निर्यात केंद्रों में बदलने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ओडीओपी का "निर्यात केंद्र के रूप में जिले (डीईएच)" के साथ विलय कर दिया गया। मार्च 2023 में शुरू की गई नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में डीईएच पर विशेष जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य 2030 तक 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल करना है।

जिला–स्तर के निर्यात का विश्लेषण

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, भारत के 760 से अधिक जिलों में से, 673 जिलों (यानी 88.5% जिलों) ने वित्तीय वर्ष 2023 में उत्पादों का निर्यात किया। इसमें सबसे अधिक निर्यात जामनगर से किया गया, जो भारत के निर्यात का 15.9% था। शीर्ष 10 निर्यातक जिले यानी जामनगर (16%), सूरत (4%), मुंबई उपनगर (4%), मुंबई (3%), कांचीपुरम (3%), पुणे (3%), भरूच (2%), गौतम बुद्ध नगर (2%), अहमदाबाद (2%), कच्छ (2%) रहे। इन सभी जिलों से वित्तीय वर्ष 2023 में भारत के निर्यात में करीब 41% का योगदान दिया गया। यह कुछ जिलों में निर्यात के उच्च संकेंद्रण को दर्शाता है।

चूंकि भारत के 2% से भी कम जिले भारत के 41% से अधिक निर्यात में योगदान करते हैं, इसलिए ओडीओपी–डीईएच पहल के तहत "निर्यात में योगदान के मामले में अनुपस्थित मध्य जिलों" का दोहन करने की उल्लेखनीय गुंजाइश बनी हुई है। इस संबंध में, भारत में कुल 59 "अनुपस्थित मध्य जिलों" की पहचान की गई है जिन्होंने 1 बिलियन यूएस डॉलर से 5 बिलियन यूएस डॉलर के बीच निर्यात में योगदान दिया है। वित्तीय वर्ष 2023 में इन जिलों की भारत के निर्यात (या 130.7 बिलियन यूएस डॉलर के निर्यात) में 29% हिस्सेदारी रही। मध्यम से लंबी अवधि में भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इन 59 जिलों को लक्षित करना बेहद महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

चुने गए जिलों में सबसे अधिक संख्या गुजरात राज्य (7 जिले) से है। इसके बाद आंध्र प्रदेश (6), महाराष्ट्र (6), ओडिशा (5), तमिलनाडु (5), हरियाणा (4), तेलंगाना (4) आदि हैं। चुने गए जिलों के लिए सबसे अधिक संयुक्त निर्यात गुजरात (18.8 बिलियन यूएस डॉलर), तमिलनाडु (14.2 बिलियन यूएस डॉलर), महाराष्ट्र (13.9 बिलियन यूएस डॉलर), आंध्र प्रदेश (11.1 बिलियन यूएस डॉलर) और तेलंगाना (9.6 बिलियन यूएस डॉलर) से हैं।

ओडीओपी–डीईएच के लिए अनुकूल योजनाओं का चयन

एमएसएमई चैंपियंस योजना

एमएसएमई चैंपियंस योजना को निम्नलिखित तीन प्रमुख घटकों के साथ तैयार किया गया है:

एमएसएमई नवोन्मेषी	• इन्क्यूबेशन, डिजाइन संबंधी उपाय और आईपीआर की सुरक्षा में नवाचार का संयोजन • मुख्य लक्ष्य नवाचार के लिए भारत की क्षमता के बारे में एमएसएमई के बीच जागरूकता बढ़ाना है।
एमएसएमई सस्टेनेबल (जेडईडी)	• जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेडईडी) की कार्यप्रणालियों के बारे में एमएसएमई के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए तैयार किया गया • जेडईडी प्रमाणन प्राप्त करने से एमएसएमई को कई लाभ प्राप्त होते हैं, जिसमें बर्बादी में पर्याप्त कमी, उत्पादकता में वृद्धि आदि शामिल है।
एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (एलईएएन)	• इसका उद्देश्य एमएसएमई की उत्पादकता, दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। • मुख्य फोकस विभिन्न प्रक्रियाओं, इन्वेंट्री प्रबंधन, स्थान का उपयोग, ऊर्जा की खपत और अन्य में अपव्यय को कम करने पर है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम– क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी)

एमएसई–सीडीपी, जिसे 2007 तक लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एसआईसीडीपी) के रूप में जाना जाता था, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा पूरे भारत में एमएसई और उनके समूहों की उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण पहल है। यह क्लस्टर विकास दृष्टिकोण पर आधारित करता है, जो चिह्नित क्षेत्रों में समान या पूरक उत्पाद बनाने वाले उद्यमों के समूहों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह एमएसई के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने हेतु सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) और बुनियादी ढांचा विकास केंद्रों (आईडीसी) को स्थापित करता है।

भारत में 11 जुलाई 2023 तक, 95 सीएफसी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, 116 कार्यरत हैं और 222 को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, बुनियादी ढांचागत विकास से जुड़ी 206 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। जबकि 126 परियोजनाओं पर काम जारी है और 335 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण (पीएमएफएमई) योजना

पीएमएफएमई योजना असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए शुरू की गई। इस क्षेत्र में लगभग 25 लाख अनौपचारिक उद्यम शामिल हैं, जो रोजगार और मूल्य संवर्धन में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। हालांकि, आधुनिक प्रौद्योगिकी, मशीनरी, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली और मार्केटिंग कौशल तक सीमित पहुंच इसके विकास में बाधा डालती है। पीएमएफएमई योजना का उद्देश्य मौजूदा सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, औपचारीकरण को बढ़ावा देना एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और उत्पादक सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करना है।

पांच वर्षों (2020–21 से 2024–25) में 10,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय के साथ, यह योजना क्रेडिट–लिंक्ड सब्सिडी प्रदान करेगी और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देगी।

चुनिंदा राज्यों द्वारा किए गए प्रयास

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के अत्यधिक महत्त्व को पहचानते हुए 2018 में ओडीओपी योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। देश में हस्तशिल्प, कालीन और चमड़े के निर्यात में राज्य का बड़ा योगदान है। सरकार ने डेटाबेस बनाने, प्रशिक्षण प्रदान करने, अनुसंधान करने सहित विभिन्न पहलें की हैं और उत्पाद विकास एवं मार्केटिंग के लिए सूक्ष्म योजनाएं बनाई हैं।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र ने 2022 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सभी 36 जिलों के विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ओडीओपी पुस्तिका जारी की। सरकार ने इस पहल के तहत 131 उत्पादों को चिह्नित किया है। ओडीओपी संवर्धन रणनीति में बुनियादी ढांचे की उपयुक्तता का आकलन करना, जीआई टैगिंग के माध्यम से उत्पादों को बढ़ावा देना और निर्यात तत्परता सूचकांक (ईपीआई) में राज्य की रैंकिंग में सुधार करना शामिल है। महाराष्ट्र बाजार तक पहुंच बनाने, संपर्क करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखला व्यवस्था स्थापित करने के लिए निर्यात संगठनों, व्यापार निकायों और दूतावासों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है।

तेलंगाना

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण (पीएमएफएमई) योजना के ओडीओपी दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में, तेलंगाना राज्य खाद्य प्रसंस्करण सोसाइटी ने प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए विशिष्ट खाद्य उत्पादों को चिह्नित किया है। राज्य सरकार के दिशा-निर्देश कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए सहायता प्रदान करने, नुकसान को कम करने, उचित परख सुनिश्चित करने और भंडारण व मार्केटिंग सुविधाओं को बढ़ाने पर केंद्रित हैं। यह योजना ओडीओपी उत्पादों के उत्पादन में लगी मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म इकाइयों को पूंजी निवेश सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता देती है।

गुजरात

जुलाई 2023 में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ओडीओपी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में स्वदेशी शिल्प और कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार के साथ सहयोग किया। कुल 33 जिलों वाला गुजरात, पारंपरिक

शिल्प और कृषि वस्तुओं सहित 68 अनूठे उत्पादों की एक विविध श्रृंखला प्रदान करता है। इस सहयोग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को एम्पोरिया की ओर ले जाना, बिक्री को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात के उत्पादों की पहुंच को बढ़ाना है। गरवी गुजरात भवन ने अपने भीतरी हिस्सों में ओडीओपी उत्पादों को भी एकीकृत किया है, इसमें गुजरात के हस्तशिल्प को बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश ने विशिष्ट चुनौतियों और प्रस्तावित उपायों के साथ-साथ ओडीओपी दृष्टिकोण के तहत संभावित निर्यात को चिह्नित किया है। उदाहरण के लिए, ऊना जिले में लाइट इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने और प्रशिक्षण पहल के माध्यम से कच्चे माल संबंधी चुनौतियों से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। निर्यात वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश एक समर्पित राज्य-स्तरीय निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ (एचपीईपीसी) की स्थापना कर रहा है। यह प्रकोष्ठ निर्यात-उन्मुख कार्यक्रमों का समन्वय करेगा, व्यापार संगठनों के साथ सहयोग करेगा और निर्यात-उन्मुख उद्योगों को मार्केटिंग में सहायता प्रदान करेगा। क्षमता निर्माण कार्यशालाएं निर्यात संबंधी ज्ञान को बढ़ाएंगी, और एक बी2बी एक्सचेंज लघु और सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करेगा।

दुनिया से सीखा

जापान

वर्ष 1979 में जापान में "एक गांव एक उत्पाद" (ओवीओपी) अभियान शुरू हुआ। यह अभियान क्षेत्रीय आर्थिक पुनरोद्धार का सफल मॉडल रहा। यह जापान के कृषि से औद्योगीकरण की दिशा में आगे बढ़ने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के सामने आने वाली चुनौतियों की वजह से उभर कर सामने आया है। ओवीओपी का दृष्टिकोण प्रत्येक गांव के अनूठे सांस्कृतिक और संसाधन से जुड़े पहलुओं को संरक्षित करते हुए स्थानीय उत्पादों को स्थानीय और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी पेशकशों में बदलने पर केंद्रित है। यह अभियान गांव की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने, स्थानीय आय बढ़ाने और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने में कारगर साबित हुआ। इसने मानव संसाधन विकास और सामाजिक मूल्यों के संरक्षण को प्राथमिकता दी, समुदाय के भीतर एक सामूहिक, सहकारी सोच को बढ़ावा दिया।

भारत की ओडीओपी परियोजना जापान के अनुभव से महत्त्वपूर्ण सबक ले सकती है, जो संपोषी आर्थिक विकास एवं सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देते हुए अपने समुदायों में गौरव और पहचान की भावना को बढ़ावा दे सकती है।

थाईलैंड

थाईलैंड का "वन टैम्बोन वन प्रोडक्ट" (ओटीओपी) कार्यक्रम जापानी ओवीओपी अभियान की तरह ही है। लेकिन यह 2001 में सरकार द्वारा शुरू किए गए टॉप-डाउन दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनः गति देना और घरेलू मांग को बढ़ावा देकर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना है।

जैसा कि भारत ओडीओपी परियोजना की संभावनाएं तलाश रहा है, यह थाईलैंड के ओटीओपी अनुभव से बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है। भारत गरीबी उन्मूलन, आर्थिक पुनरोद्धार और स्थानीय गौरव एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने जिला-आधारित कार्यक्रम को लागू कर सकता है।

मैक्सिको

मैक्सिको में 2001 में शुरू की गई "प्यूब्लोस मैजिकोस" (मैजिकल टाउन) नीति का उद्देश्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्त्व वाले गांवों व कस्बों को बढ़ावा देना और उन्हें पुनर्जीवित करना है। यह प्रमुख शहरों और समुद्र तटों के अलावा पर्यटन को प्रोत्साहित करता है, देश की पर्यटन पेशकशों में विविधता लाता है और ग्रामीण क्षेत्रों तक आर्थिक लाभ को पहुंचाता है। चयन प्रक्रिया में विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले शहरों के प्रतिस्पर्धात्मक आवेदन शामिल हैं। इनमें जनसंख्या का आकार, सभी सुविधाओं से लैस शहरों से निकटता, अनूठी सांस्कृतिक या प्राकृतिक विशेषताएं शामिल हैं। यह कार्यक्रम पर्यटन को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और मैक्सिको की सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने में सफल रहा है।

भारत की ओडीओपी परियोजना मैक्सिको की "प्यूब्लोस मैजिकोस" पहल से महत्त्वपूर्ण सीख भी ले सकती है। स्थानीय संस्कृति व विरासत को संरक्षित करने एवं उसका उत्सव मनाते हुए स्थानीय पर्यटन व आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने जिलों की अनूठी विशेषताओं का लाभ उठा सकती है।

फिलीपींस

फिलीपींस में "एक नगर, एक उत्पाद" (ओटीओपी) कार्यक्रम 2004 में शुरू किया गया। यह एक सफल ग्रामीण आर्थिक विकास कार्यक्रम रहा है। यह कार्यक्रम स्थानीय समुदायों को सहायता प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए स्थानीय सरकारी इकाइयों, राष्ट्रीय सरकारी एजेंसियों और निजी क्षेत्र को एक साथ लाता है। इसकी सफलता में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में स्थानीय सरकारों का समर्पण, स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, स्थानीय प्रतिभा और कौशल की प्रचुरता, उत्पादों के लिए व्यवस्थित बाजार एवं प्रभावी सरकारी सेवा का सामंजस्य शामिल है।

चूंकि भारत ने अपनी स्वयं की "ओडीओपी" परियोजना शुरू की है, ऐसे में वह फिलीपींस की ओटीओपी की उपलब्धियों से सीख सकता है। भारत के विविध जिलों में समावेश और संपोषी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी, क्षमता निर्माण और बाजार संवर्धन के महत्त्व पर जोर देना महत्त्वपूर्ण होगा।

आगे की राह

ओडीओपी-डीईएच भारत की एक अभूतपूर्व पहल है। इसका यदि अच्छी तरह उपयोग और क्रियान्वयन किया जाए तो पूरे देश को संपूर्ण लाभ मिल सकता है। इस पहल में निवेश और व्यापार विस्तार के लिए अनुकूल माहौल बनाने के मकसद से केंद्र और राज्य सरकारों एवं स्थानीय हितधारकों के बीच सहयोग होना चाहिए। इस पहल को सफल बनाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, कौशल-निर्माण और डिजिटलीकरण जैसी चुनौतियों का समाधान करना होगा। नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपनाकर, भारत अपने जिलों को वैश्विक स्तर पर आकर्षक विनिर्माण एवं निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है। इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों की क्षमता का अधिकतम उपयोग करते हुए देश की सांस्कृतिक विविधता का लाभ उठाने की क्षमता है, जिससे संपोषी आर्थिक विकास हो सके। ■

भारत–कनाडा आर्थिक संबंधों को बढ़ाना : रुझान और संभावनाएं

– **सारा जॉय,** *मुख्य प्रबंधक*
सृजिता नंदी, *उप–प्रबंधक*

कनाडा विश्व की आठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2022 में मौजूदा कीमतों पर उसका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर रहने का अनुमान है। लगभग 38 मिलियन लोगों की आबादी है और 2022 में ही मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति जीडीपी 56,794 यूएस डॉलर होने का अनुमान है। कनाडा एक उच्च आय वाला देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र (इसकी जीडीपी में 72.4% हिस्सेदारी) का वर्चस्व है। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र (25.7%) और कृषि क्षेत्र (1.9%) का स्थान है।

भारत–कनाडा वस्तु व्यापार

भारत–कनाडा द्विपक्षीय संबंध आर्थिक संबंधों के विस्तार पर आधारित है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 2010 में 3.3 बिलियन यूएस डॉलर का रहा, जो 2015 में बढ़कर 5.9 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया और 2017 में 7.2 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया। वर्ष 2017 में कनाडा से आयात 4.8 बिलियन यूएस डॉलर (कच्चे हीरों के बढ़ते आयात के कारण) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहा और व्यापार घाटा भी सबसे अधिक 2.5 बिलियन यूएस डॉलर रहा। कोविड–19 की वजह से 2020 में वैश्विक आर्थिक व्यवधानों के कारण, कुल व्यापार पिछले वर्ष के 6.8 बिलियन यूएस डॉलर से घटकर 5.6 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। हालांकि, कनाडा से आयात की तुलना में भारत का निर्यात अधिक लचीला रहा। दोनों देशों के बीच 2021 में व्यापार में और तेजी देखी गई और कुल व्यापार 6.3 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया। इसमें 3.6 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात और 2.7 बिलियन यूएस डॉलर का आयात शामिल है। कनाडा के साथ भारत का वस्तु व्यापार अधिशेष 2021 में 841.6 मिलियन यूएस डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 2021 में, भारत कनाडा का 14वां सबसे बड़ा निर्यात स्थल, 13वां सबसे बड़ा आयात स्रोत और कुल मिलाकर 13वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा।

भारत–कनाडा सेवा व्यापार

भारत के साथ कनाडा का कुल सेवा व्यापार 2010 में 1.1 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2020 में 5.5 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। कनाडा ने शुरू में भारत के साथ सेवा व्यापार घाटे को बनाए रखा, जो बाद में 2014 से अधिशेष में बदल गया। इसका कारण भारत से सेवाओं के आयात की तुलना में कनाडा से सेवाओं के निर्यात में वृद्धि की तेज दर है। भारत 2020 के दौरान कनाडा के सेवा निर्यात के लिए 5वां सबसे बड़ा स्थल रहा। भारत में कनाडा का सेवा निर्यात पिछले दशक में लगातार बढ़ा है। यह 2010 में 0.5 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2020 में 3.7 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। भारत में कनाडा का सेवा निर्यात 2019 में उच्चतम रहा। वर्ष 2020 में भारत में कनाडा के कुल सेवाओं के निर्यात में यात्रा सेवाओं की सर्वाधिक 88.5% हिस्सेदारी रही। भारत में कनाडा के निर्यात में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले अन्य क्षेत्रों में अन्य प्रोफेशनल सेवाएं (4.2%) और परिवहन (2.3%) शामिल रहे।

वर्ष 2020 में, कनाडा के कुल सेवा आयात में 1.8% की हिस्सेदारी के साथ, भारत कनाडा का 9वां सबसे बड़ा सेवा आपूर्तिकर्ता रहा। वर्ष 2010–2020 के दौरान, भारत से कुल सेवाओं का आयात 0.6 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 1.8 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। भारत से कनाडा की सेवाओं के आयात में मुख्य रूप से वाणिज्यिक सेवाएं शामिल हैं, जिनमें सरकारी सेवाओं की हिस्सेदारी नगण्य है। भारत से आयात होने वाली सेवाओं में दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं की हिस्सेदारी 41.3% (92.4% कंप्यूटर सेवाओं का योगदान) है। इसके बाद अन्य व्यावसायिक सेवाएं (38.1%) और यात्रा (10.7%) हैं। मोटे तौर पर, तकनीकी, व्यापार–संबंधी और अन्य व्यावसायिक सेवाओं का भारत से व्यापार सेवाओं के आयात का 42.9% हिस्सा है। फिर पेशेवर और प्रबंधन परामर्श सेवाएं (29.2%) और अनुसंधान एवं विकास सेवाएं (22.7%) हैं। तकनीकी, व्यापार–संबंधी और अन्य व्यावसायिक सेवाओं में– वास्तुशिल्प, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक और अन्य तकनीकी सेवाएं, अपशिष्ट शोधन और प्रदूषण को कम करना, कृषि व खनन सेवाएं, परिचालन लीजिंग सेवाएं, व्यापार–संबंधी सेवाएं और अन्य व्यावसायिक सेवाएं शामिल हैं।

भारत–कनाडा द्विपक्षीय निवेश

फायनैंशल टाइम्स के एफडीआई मार्केट्स डेटाबेस के अनुसार, 2010–2021 के दौरान, कनाडा में 66 भारतीय कंपनियों की 103 परियोजनाओं में भारत का कुल पूंजी निवेश 5.8 बिलियन यूएस डॉलर की संचयी राशि के साथ रहा। इससे कनाडा में 16,989 रोजगारों का सृजन हुआ। पूंजी निवेश के मामले में, सबसे बड़ी हिस्सेदारी सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाओं में रही, इसके बाद रसायन और धातु आदि शामिल रहे।

जबकि 2010–2021 के दौरान ही, 88 कनाडाई कंपनियों द्वारा 121 परियोजनाओं के तहत भारत में 3.2 बिलियन यूएस डॉलर का संचयी निवेश किया गया। इससे भारत में 25,314 रोजगारों का सृजन हुआ। निवेश के मामले में, बड़ी हिस्सेदारी सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा क्षेत्र में रही है। इसके बाद धातु, नवीकरणीय ऊर्जा और वित्तीय सेवाओं का स्थान रहा।

कनाडा के साथ भारत के व्यापार संबंधों को बढ़ाने के अवसर

इंडिया एक्ज़िम बैंक के शोध अध्ययन में 2015 से 2021 की अवधि के आंकड़ों के आधार पर प्रकट तुलनात्मक लाभ पद्धति का उपयोग करके कनाडा के साथ भारत के व्यापार संबंधों को बढ़ाने के अवसरों का विश्लेषण किया गया है। भारत से कनाडा को 1 मिलियन यूएस डॉलर के न्यूनतम निर्यात वाले उत्पादों में से, 559 उत्पादों को चिह्नित किया गया है। इनका भारत से कनाडा को कुल निर्यात 3.2 बिलियन यूएस डॉलर का है। जबकि उन्हीं उत्पादों में कनाडा का वैश्विक आयात 2021 में 93.6 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। एचएस 10–अंकीय स्तर पर 559 वस्तुओं में से, 324 वस्तुएं उत्पाद चैंपियन की श्रेणी में आती हैं। भारत से कनाडा को इन वस्तुओं का संयुक्त निर्यात 2021 में 2.2 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। यह कनाडा को भारत के निर्यात का लगभग 45.9% रहा। इसके बाद कनाडा को 101.5 मिलियन यूएस डॉलर मूल्य के भारत के निर्यात के साथ 41 वस्तुओं के साथ कम उपलब्धि हासिल हुई। कनाडा को भारत के कुल निर्यात में इन उत्पादों की न्यूनतम हिस्सेदारी 2.1% है। ये ऐसे उत्पाद हैं, जिनकी कनाडा के बाजार में आयात मांग बढ़ रही है, लेकिन भारत के पास अपने निर्यात में आवश्यक प्रतिस्पर्धात्मकता नहीं है। उत्पाद चैंपियन पर ध्यान केंद्रित करके अल्पावधि में कनाडा में भारत के निर्यात को बढ़ाया जा सकता है। जबकि उत्पादों की कम उपलब्धि वाली श्रेणी को बढ़ावा देने से मध्यम से लंबी अवधि में भारत के निर्यात में बढ़ोतरी हो सकती है। अध्ययन में भारत से निर्यात बढ़ाने के लिए एचएस 10–अंकीय स्तर पर संभावित उत्पादों की पहचान की गई है। इसमें मशीनरी, हीरे जैसे कीमती रत्न और आभूषण, फार्मासूटिकल उत्पाद, जमे हुए खाद्य उत्पाद, चावल, भारी वाहन और उनके कलपुर्जे तथा निर्माण मशीनरी जैसे अन्य क्षेत्र शामिल हैं।

दोनों देशों के तुलनात्मक टैरिफ विश्लेषण निम्नलिखित दर्शाते हैं–

कनाडा से आयात पर भारत द्वारा लगाया जाने वाला शुल्क (टैरिफ)

ऐसी 160 टैरिफ लाइनें (6–अंकीय एचएस कोड स्तर पर) हैं, जिनमें प्रभावी रूप से 0% की शुल्क दर लागू है, जो 2021 में 309.4 मिलियन यूएस डॉलर के कुल आयात की राशि है। यह 2021 में कनाडा से कुल आयात का 11.4% है। जबकि 0.1% और 10% के टैरिफ स्तरों के बीच, कुल आयात 1.6 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। यह 2021 में आयात के 60.2% के अनुरुप रहा। संचयी रूप से, कनाडा से 90% भारतीय आयात को 50 से कम की प्रभावी रूप से लागू शुल्क दर लगाई गई। वहीं, जिन उत्पादों को भारत द्वारा लगाए गए उच्चतम प्रभावी टैरिफ का सामना करना पड़ा, जो 50% से अधिक हैं, वे चैप्टर्स– एचएस–04, एचएस–07, एचएस–08, एचएस–09, एचएस–17, एचएस–21, एचएस–22, एचएस–87 और एचएस–95 (ज्यादातर कृषि उत्पाद, पेय पदार्थ और ऑटो तथा ऑटो घटक) में शामिल हैं।

भारत से आयात पर कनाडा द्वारा लगाया जाने वाला शुल्क

2873 टैरिफ लाइनें (6–अंकीय एचएस कोड स्तर पर) हैं, जिनकी मात्रा 2021 में 2.9 बिलियन यूएस डॉलर रही। इन पर कनाडा शून्य % का प्रभावी रूप से लागू टैरिफ लगाता है। ये उत्पाद 2021 में भारत से कनाडा के आयात का 61.8% हिस्सा हैं। वहीं 0.1%-10% प्रभावी रूप से लागू टैरिफ स्तर श्रेणी में 1.2 बिलियन यूएस डॉलर की 1595 टैरिफ लाइनें हैं, जो 2021 में भारत से कनाडा के 24% से अधिक आयात के अनुरूप हैं। इसलिए संचयी रूप से, भारत से कनाडा के 86% आयात पर 10% से कम का प्रभावी रूप से लागू शुल्क रहा। वर्ष 2021 में 13% की कुल आयात हिस्सेदारी के साथ, 432 टैरिफ लाइनों को 10.1%-20% के बीच प्रभावी रूप से लागू शुल्क के दायरे में रखा गया।

दिसंबर 2022 तक, कनाडा ने डब्ल्यूटीओ सदस्यों (भारत सहित) पर 2319 गैर–टैरिफ उपाय (एनटीएम) लगाए हैं। साथ ही कनाडा द्वारा भारत पर द्विपक्षीय रूप से एनटीएम लगाए गए हैं। इनमें सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (एसपीएस) व व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) से जुड़े उपाय सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले एनटीएम में से हैं। इनमें 1424 एसपीएस (74 लागू और 1350 शुरू किए गए) और 799 टीबीटी (191 लागू और 608 शुरू किए गए) हैं। कनाडा ने मात्रात्मक प्रतिबंध, टैरिफ–दर कोटा, निर्यात सब्सिडी, एंटी–डंपिंग उपाय और काउंटरवेलिंग उपाय आदि भी अपनाए हैं।

सहयोग के संभावित क्षेत्र

भारत और कनाडा मंत्रिस्तरीय–रणनीतिक व्यापार एवं ऊर्जा वार्ता, विदेश कार्यालय परामर्श और क्षेत्र विशिष्ट संयुक्त कार्य समूहों सहित विभिन्न तंत्रों के माध्यम से अपने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत और कनाडा ने रेल, परिवहन, नागरिक उड्डयन, कौशल विकास, यूरेनियम अयस्क खरीद, परमाणु सहयोग, आईसीटी, ऊर्जा, आईपीआर, उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। निवेश संवर्धन और सुविधा पर इन्वेस्ट इंडिया एवं इन्वेस्टमेंट ब्यूरो, ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। कनाडा में भारतीय कंपनियां सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, इस्पात, प्राकृतिक संसाधन और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं। दोनों देश विदेशी निवेश संवर्धन और संरक्षण करार (एफआईपीए) पर हस्ताक्षर करने की संभावना तलाश रहे हैं।

इस अध्ययन में भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए ऊर्जा (परमाणु ऊर्जा एवं हाइड्रोजन सहित सौर एवं स्वच्छ ऊर्जा सहित नवीकरणीय), कृषि और संबद्ध क्षेत्रों (खाद्य प्रसंस्करण, कृषि प्रौद्योगिकी और उपकरण एवं उर्वरक), इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितकी तंत्र, बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर, रोबोटिक्स, आईसीटी एवं चिकित्सा उपकरण प्रौद्योगिकियों सहित उन्नत विनिर्माण जैसे संभावित क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है। कनाडा के साथ पारस्परिक समझौते करने से नियामक मानकों, अनुरूपता आकलन, मान्यता प्रक्रियाओं, योग्यता, वीजा और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। ■

अफ्रीका में भारत की निवेश संबंधी संभावनाएं

– **राहुल मजूमदार**, *सहायक महाप्रबंधक*
साक्षी गर्ग, *उप–प्रबंधक*

अफ्रीका के प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और तेजी से बढ़ती मध्यमवर्गीय आबादी का संयोजन इस महाद्वीप को एक आकर्षक बाजार और एक बेहतर निवेश स्थल बनाते हैं। यहाँ 2023 और 2024 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि औसतन 4% के आसपास रहने का अनुमान है। अफ्रीका आर्थिक विकास में बाकी दुनिया से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार समझौता (एएफसीएफटीए) एक बड़े बाजार की स्थापना करके और अधिक आर्थिक अवसर प्रदान करता है।

भारत–अफ्रीका व्यापार संबंध

अफ्रीका के साथ भारत का कुल व्यापार 2002 के 6.3 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2021 में 82.5 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। भारत के वैश्विक निर्यात और आयात में अफ्रीका की हिस्सेदारी क्रमशः 9.6% और 7.8% रही। अफ्रीका के वैश्विक निर्यात और आयात में भारत का योगदान क्रमशः 6% और 5.6% रहा। वहीं 2021 में अफ्रीका को भारत के निर्यात का मूल्य 37.9 बिलियन यूएस डॉलर रहा। जबकि आयात का मूल्य 44.6 बिलियन यूएस डॉलर रहा। अफ्रीका में 2021 में भारत की शीर्ष निर्यात श्रेणियां खनिज, ईंधन और तेल, ऑटोमोबाइल और फार्मासूटिकल्स रहीं। अफ्रीका से 2021 में ही भारत के आयात का लगभग आधा हिस्सा कच्चे तेल का रहा।

इस क्षेत्र में भारत का शीर्ष निर्यात भागीदार दक्षिण अफ्रीका है। इसके बाद नाइजीरिया, मिस्र, टोगो और केन्या हैं। दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया अफ्रीका में भारत के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण आयात स्रोत हैं, जिनकी अफ्रीका से आयात में हिस्सेदारी 45% है।

भारत–अफ्रीका व्यापार करार

अल्प विकसित देशों के लिए भारत की ड्यूटी–फ्री टैरिफ तरजीही योजना (डीएफटीपी–एलडीसी) के तहत भारत की लगभग 98.2% टैरिफ लाइनों पर ड्यूटी–फ्री/तरजीही बाजार पहुंच प्रदान की जाती है। चूंकि इस योजना के तहत 34 लाभार्थियों में से 26 अफ्रीकी देश हैं, ऐसे में एकपक्षीय तरजीही व्यवहार ने भारत और अफ्रीका के बीच मजबूत व्यापार संबंधों में काफी मदद की है।

इसके अलावा, भारत–मॉरीशस व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (सीईपीए) भारत द्वारा किसी अफ्रीकी देश के साथ हस्ताक्षरित पहला समझौता है। वस्तुओं के व्यापार, मूल नियम, सेवाओं में व्यापार, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों सहित अन्य को कवर करते हुए यह एक सीमित करार है, जो अप्रैल 2021 में लागू हुआ। दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (एसएसीयू) के बीच तरजीही व्यापार समझौते के लिए 2007 में बातचीत शुरू हुई। उसे 2020 में पुनः शुरू किया गया।

अफ्रीका में भारत का निवेश

अप्रैल 2000 से जनवरी 2023 के दौरान अफ्रीका में भारत का कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) 50.4 बिलियन यूएस डॉलर रहा। इस अवधि के दौरान, मॉरीशस अफ्रीका में भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा। इसके टैक्स हेवन स्टेटस के कारण, अफ्रीका में भारत के कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 79.1% की हिस्सेदारी रही। इस अवधि के दौरान अन्य शीर्ष प्राप्तकर्ता मोजाम्बिक (7%), सूडान (6%), दक्षिण अफ्रीका (2%) और मिस्र (1.3%) रहे। अफ्रीका में भारतीय निवेश विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसमें विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। अन्य लाभप्रद क्षेत्र वित्तीय, बीमा, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सेवाएं, कृषि, खनन आदि हैं।

अफ्रीका में भारतीय कंपनियों की फर्म आधारित समीक्षा

अनुमान है कि भावी भारतीय निवेशक कच्चे माल की सुरक्षा और स्थिरता, कच्चे माल की लागत, बाजार के आकार, आकर्षक आंतरिक निवेश नीतियां, लाभ के प्रत्यावर्तन, राजनीतिक स्थिरता और अफ्रीका में निवेश के लिए कानूनी प्रणाली जैसे कारकों को अधिक महत्त्व देते हैं। तीसरे देश के बाजारों तक पहुंच, वित्तीय बाजारों तक पहुंच और प्रबंधन कार्यप्रणालियों, श्रम कानूनों और जनशक्ति की गुणवत्ता जैसे मानव संसाधन मापदंडों को भी पर्याप्त महत्त्व दिया जाता है।

भारतीय कंपनियों के निवेश के बाद के अनुभव से पता चलता है कि श्रम कानून, प्रबंधन कार्यप्रणालियों, जनशक्ति गुणवत्ता और कर व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सुधार की काफी गुंजाइश है। आगे ये सुनिश्चित हुआ कि अफ्रीका में निवेश हेतु भारतीय कंपनियों के लिए संयुक्त उद्यम सबसे प्रमुख रूट हो सकता है। इसके अलावा, एएफसीएफटीए से भारतीय व्यवसायों के लिए महत्त्वपूर्ण अवसर बनने की उम्मीद है क्योंकि यह अंतर–क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। कुल मिलाकर, अफ्रीकी बाजार उत्पाद स्वीकार्यता के साथ–साथ राजस्व सृजन दोनों के मामले में भारतीय कंपनियों के लिए अनुकूल रहा है। यह काफी हद तक इस उम्मीद के अनुरूप है कि अफ्रीका एक बढ़ता हुआ बाजार है और इसकी जरूरतें वैसी ही हैं जैसी भारत ने देखी है या वर्तमान में अनुभव कर रहा है।

अफ्रीका में निवेश के अवसर: लक्षित अर्थव्यवस्थाएं

अफ्रीका के साथ भागीदारी भारत के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है। भारत के लिए अफ्रीकी क्षेत्र के साथ अपनी भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए पारंपरिक क्षेत्रों से इतर अतिरिक्त बाजारों का पता लगाना महत्त्वपूर्ण है। अफ्रीका में शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं को चिह्नित किया गया है, जो भारत के लिए उच्च निवेश के अवसर प्रदान करती है। इन अर्थव्यवस्थाओं को तीन समूहों में बांटा जा सकता है

- श्रेणी ए (यलो : उच्च रेटिंग और निवेश की संभावना वाले देश) जैसे बोत्सवाना,
- श्रेणी बी (ब्लू : उपरोक्त फिल्टर का उपयोग करके बिना किसी महत्त्वपूर्ण समस्या के चुने गए देश), और
- श्रेणी सी (ऑरेंज : उपरोक्त फिल्टर का उपयोग करके चुने गए देशों में प्रत्यावर्तन, एफएटीएफ निगरानी आदि मुद्दे हैं) दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया आदि।

भारत के लिए उपयुक्त व्यावसायिक अवसरों वाली लक्षित अर्थव्यवस्थाएं

क्र. सं.	श्रेणी	देश	जीडीपी (स्थिर 2015 यूएस डॉलर) बिलियन यूएस डॉलर	एफडीआई (बिलियन यूएस डॉलर) (2010-21)	निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर) 2021	भारत का निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर): 2021	आयात में भारत की हिस्सेदारी: 2021	संभावित उद्योग	रेटिंग (दिसंबर 2022 तक)
1	सी	दक्षिण अफ्रीका	353.3	87.0	123.7	6.0	5.7%	कोल्ड स्टोरेज, बीयर और वाइन, मेडिकल प्लास्टिक और डिस्पोजेबल प्लास्टिक, वाहन, मशीनरी, वस्त्र और रसायन	बीए2/स्थिर
2	बी	कोत दि'वार	65.3	7.5	14.0	0.7	5.1%	कृषि-प्रसंस्करण, फार्मासूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, आईटी, और वस्त्र	बीए3/ सकारात्मक
3	सी	तंजानिया	64.2	15.5	6.4	1.7	11.1%	सिंचाई प्रणाली, कृषि प्रशिक्षण और क्षमता, परिवहन, अवसंरचना, संचार, बिजली (विशेष रूप से नवीकरणीय स्रोत), थोक और खुदरा व्यापार, और ट्रैवल एवं टूरिज्म	बी2/ सकारात्मक
4	बी	मिस्र	426.0	71.4	40.7	3.3	3.3%	पशुपालन, मत्स्य पालन, ऑटोमोबाइल, नवीकरणीय ऊर्जा और रसायन	बी2/ नकारात्मक
5	बी	केन्या	90.4	17.2	6.8	2.5	10.8%	कीटनाशक, उर्वरक, बागवानी, चाय, कॉफी, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार और चिकित्सा उपकरण	बी2/ नकारात्मक
6	बी	मोज़ाम्बिक	18.4	45.1	5.1	1.8	8.6%	स्थायी सिंचाई प्रणाली, सेकेंड-हैंड उपकरण और मशीनरी, कोल्ड चेन सॉल्यूशन, कृषि-प्रसंस्करण, पैकेजिंग, डिजाइन और निर्माण, एफएमसीजी, तेल और गैस और परिवहन	सीएए2/ सकारात्मक
7	बी	कैमरून	39.0	7.8	5.7	0.4	3.4%	बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे, बॉक्साइट और तेल एवं गैस	बी2/स्थिर
8	सी	माली	16.3	5.4	9.4	0.2	3.1%	मीट, मैटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सोना, तेल और गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, ऑटोमोबाइल (विशेष रूप से दोपहिया वाहन), और जेनेरिक दवाएं	सीएए2/ स्थिर
9	बी	ट्यूनीशिया	47.0	12.4	16.4	0.4	1.9%	सोयाबीन और कच्चे वनस्पति तेल, चारा अनाज और योजक, संशोधित स्टार्च आदि सहित कृषि-प्रसंस्करण उद्योग, ट्रैक्टर, फार्मासूटिकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा, मशीनरी और पर्यटन एवं आतिथ्य	सीएए1/ डाउनग्रेड के लिए समीक्षा
10	बी	घाना	66.1	35.9	15.1	1.1	5.6%	खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, कॉस्मेटिक्स, स्वास्थ्य सेवा, खनन उद्योग उपकरण और आईसीटी	सीए/स्थिर
11	बी	मोरक्को	123.9	30.7	36.6	0.8	1.8%	मत्स्य पालन, ऊर्जा, वस्त्र, ऑटो घटक, अवसंरचना, एयरोस्पेस, स्वास्थ्य सेवा, आईसीटी और दूरसंचार	बीए1/स्थिर
12	बी	जाम्बिया	24.5	11.9	11.2	0.3	6.2%	सिंचाई प्रणाली, कृषि इनपुट और उपकरण, ऊर्जा, आईसीटी, खनन और खनिज, चिकित्सा उपकरण और पर्यटन	सीए/स्थिर
13	सी	नाइजीरिया	518.5	51.7	47.6	4.5	8.8%	तेल एवं गैस, ऑटोमोबाइल, रसायन, विद्युत, अवसंरचना, उपभोक्ता उत्पाद और आईसीटी	बी3/ डाउनग्रेड के लिए समीक्षा
14	बी	अल्जीरिया	174.2	16.7	37.9	0.7	2.1%	अनाज, डेयरी, विद्युत, आईसीटी और अवसंरचना	-
15	बी	डीआर कांगो (डीआरसी)	48.1	22.7	22.3	0.6	6.8%	मत्स्य पालन, पाम ऑयल, रबर, भंडारण, परिवहन, तांबा, कोबाल्ट और दूरसंचार	बी3/स्थिर
16	ए	बोत्सवाना	16.5	2.5	7.4	0.3	4.7%	कृषि अनुसंधान एवं विकास, ऊर्जा, खनन एवं खनिज, दूरसंचार, और चिकित्सा उपकरण और फार्मासूटिकल्स	ए3/स्थिर

भारत और बांग्लादेश के बीच घनिष्ठ सहयोग के अवसर

– **सारा जॉय**, *मुख्य प्रबंधक*
अल्फिया अंसारी, *उप–प्रबंधक*

भारत की "पड़ोसी देश पहले" की नीति के अनुरूप बांग्लादेश भारत का एक महत्त्वपूर्ण विकास साझीदार है। भारत–बांग्लादेश के मजबूत द्विपक्षीय संबंध अवसंरचना, कनेक्टिविटी, विद्युत और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर केंद्रित हैं। हालांकि, द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने के लिए बांग्लादेश के साथ भारत के लगातार व्यापार अधिशेष को ध्यान में रखना महत्त्वपूर्ण है। भारत के साथ बांग्लादेश का व्यापार घाटा आंशिक रूप से आरएमजी क्षेत्र जैसे इसके प्रमुख निर्यातों में उपयोग की जाने वाली मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात से उत्पन्न हुआ है। भारत के साथ यह व्यापार घाटा बांग्लादेश को अन्य प्रमुख बाजारों के साथ व्यापार के माध्यम से आरएमजी क्षेत्र में व्यापार अधिशेष हासिल करने की सुविधा देता है। संतुलित और सतत द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि के लिए इस व्यापार अधिशेष को ध्यान में रखना आवश्यक है। भारत–बांग्लादेश आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है:

मोटर वाहन करार का तेजी से कार्यान्वयन (2015)

बांग्लादेश–भारत सीमा दुनिया की सबसे लंबी सीमा में से एक है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार जर्मनी के साथ व्यापार की तुलना में अधिक महंगा हो जाता है। वर्ष 2021 में, द्विपक्षीय व्यापार बांग्लादेश के व्यापार का केवल 12.1% और भारत के व्यापार का 1.6% रहा, जो पूर्वी एशियाई और उप–सहारा अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं में अंतर–क्षेत्रीय व्यापार की तुलना में काफी कम रहा। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 80% भू-व्यापार बेनापोल और पेट्रोपोल भू-बंदरगाहों के माध्यम से होता है, जो एशिया में प्रमुख व्यापार जंक्शन हैं। परिवहन एकीकरण की कमी का मतलब है कि भारतीय ट्रक बांग्लादेश से पारगमन नहीं कर सकते हैं, जिससे उन्हें लंबे और महंगे मार्गों पर जाना पड़ता है।

व्यापार में सुधार के लिए, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी), सड़क, वायुमार्ग और रेल लिंक जैसे सीमा पर बुनियादी ढांचे को बढ़ाना आवश्यक है। इस तरह के सुधारों से कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, उत्पादन नेटवर्क और मूल्य श्रृंखला मजबूत होगी, व्यापारिक लागत कम होगी, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और गरीबी कम होगी। बीबीआईएन (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल) देशों में मोटर वाहन करार (एमवीए) के उम्मीदों से भरे होने के बावजूद, दक्षिण एशिया में पूरी तरह से एकीकृत सीमा पार सड़क परिवहन बाजार बनाने की क्षमता हासिल करने के लिए आगे की बातचीत और प्रोटोकॉल की आवश्यकता है। इसकी सफलता के लिए तकनीकी पहलुओं, माल ढुलाई संबंधी आवश्यकताओं और चालक की योग्यता व लाइसेंसिंग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

तटीय नौवहन करार में संशोधन

बांग्लादेश और भारत ने 2015 में तटीय नौवहन संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य सीधे अपने बंदरगाहों के बीच नदी–समुद्री जहाजों (आरएसवी) के माध्यम से माल (कार्गो) की आवाजाही को सुव्यवस्थित करना था। हालांकि, इस करार को, खासकर बंगाल की खाड़ी में खराब समुद्री परिस्थितियों के दौरान, लंबे मार्गों के लिए छोटे जहाजों के आकार संबंधी प्रतिबंधों और लागत संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तटीय परिवहन को बढ़ाने के लिए, चटगांव से पनगांव/नारायणगंज बंदरगाहों तक निश्चित बार्ज कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जिससे खाली कार्गो के लौटते फेरों की संख्या कम होगी और दोनों देशों के लिए समग्र लॉजिस्टिक्स लागत कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, आकार संबंधी प्रतिबंधों को हटाने और तीसरे पक्ष के निर्यात–आयात माल ढुलाई की अनुमति देने से तटीय नौवहन समझौते का बेहतर कार्यान्वयन हो सकता है। सीमा पार व्यापार के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों का लाभ उठाने के लिए तकनीकी मानकों में सामंजस्य स्थापित करना और व्यापार अवसंरचना में सुधार करना महत्त्वपूर्ण है।

खाद्य सुरक्षा मानकों के लिए पारस्परिक मान्यता करार

चीनी, अंगूर, आलू जैसी वस्तुओं में अलग–अलग खाद्य मानक भारत और बांग्लादेश के बीच कृषि व्यापार के लिए बाधाओं में से एक हैं। इनका समाधान दोनों देशों को पारस्परिक मान्यता करार (एमआरए) के जरिए करना चाहिए। इसे लागू करने के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और बांग्लादेश मानक एवं परीक्षण संस्थान (बीएसटीआई) चयनित कृषि उत्पादों के लिए मानकों और तकनीकी नियमों के सामंजस्य की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक तकनीकी कार्य समूह की स्थापना कर सकते हैं। बीएसटीआई और बीआईएस पारस्परिक मान्यता समझौते के माध्यम से नियामक मानकों के सामंजस्य के लिए विकसित देशों के मानकों से संबंधित संस्थानों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। गैर–अनुपालन की लागत को कम करने के लिए फूड प्रेपरेशन और पैकेजिंग में मानकों पर उत्पादवार नियमों को दोनों देशों द्वारा मैप किया जाना चाहिए। दोनों देशों को अपने खाद्य मानकों को कोडेक्स जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए।

पैरा–टैरिफ में कमी और मौजूदा सीमा शुल्क टैरिफ संरचनाओं के साथ एकीकरण

पैरा–टैरिफ को सीमा शुल्क के अलावा आयात करों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका सुरक्षात्मक प्रभाव होता है। पैरा–टैरिफ को अक्सर छुपाया जाता है, कम रिपोर्ट किया जाता है और कुछ मामलों में, समग्र सुरक्षा स्तर डब्ल्यूटीओ के तहत निर्धारित टैरिफ बाइंडिंग से भी अधिक है। बांग्लादेश ने सीमा शुल्क के शीर्ष पर कई पैरा–टैरिफ के उपयोग के माध्यम से, कई आयात प्रतिस्थापन उद्योगों के लिए सुरक्षा स्तर को और बढ़ा दिया है। पैरा–टैरिफ को सभी बैंडों में लागू किया जाता है, जिससे आयात करों में वृद्धि होती है और कभी–कभी डब्ल्यूटीओ की निर्धारित दरों से भी अधिक हो जाती है। यदि पैरा–टैरिफ को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयात शुल्क (2021 में 14%) दोगुना हो जाता है। पैरा–टैरिफ साफ्टा के तहत चरणबद्ध कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं। पैरा–टैरिफ की समस्या का पूरी तरह समाधान करने की आवश्यकता है और उन्मूलन के लिए एक अनुसूची निर्धारित की जानी चाहिए।

टेक्सटाइल वेल्यू चेन लिंकेज को एकीकृत करना

टेक्सटाइल और क्लोदिंग (टी एंड सी) क्षेत्र भारत व बांग्लादेश के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार और रोजगार का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें दोनों देशों के बीच महत्त्वपूर्ण मूल्य श्रृंखला संपर्क है। भारत अपस्ट्रीम सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हुए रेशम, कपास, धागे और कपड़े जैसी मध्यवर्ती वस्तुओं की आपूर्ति करने में उत्कृष्ट है। दूसरी ओर, बांग्लादेश डाउनस्ट्रीम फाइनल परिधान खंड में उत्कृष्ट है, जो विश्व स्तर के साथ–साथ भारत को भी निर्यात करता है। हालांकि, मौजूदा टैरिफ, गैर–टैरिफ संबंधी बाधाएं और परिवहन अक्षमताएं मूल्य श्रृंखला संपर्क के विकास में बाधा डालती हैं। सीमा बिंदुओं पर देरी, खराब बुनियादी ढांचे और नियामक बाधाओं के कारण मध्यवर्ती उत्पादों की लागत बढ़ जाती है, जिससे दक्षिणपूर्व और पूर्वी एशियाई उत्पादन नेटवर्क के साथ एकीकरण चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वस्त्रों में एक मजबूत क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना महत्त्वपूर्ण है। इसके अलावा, डिजाइन और फैशन प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना के लिए सहयोग दोनों देशों को प्रमुख फैशन केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है।

कृषि और कृषि–प्रसंस्करण में क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं का सुदृढ़ीकरण

भारत और बांग्लादेश के बीच कृषि–प्रसंस्करण, रसायन, फार्मासूटिकल्स, परिधान और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला (आरवीसी) की क्षमता निहित है। बीज उत्पादन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और अनुसंधान एवं विकास को शामिल करते हुए कृषि मूल्य श्रृंखला में सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। कृषि आदानों, उपकरणों और फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में निवेश की संभावनाएं मौजूद हैं। संयुक्त उद्यम व्यापार घाटे को कम करने और बांग्लादेश के लिए उद्योग एवं बाजार में विविधता लाने में मदद कर सकते हैं। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, अपने प्रचुर कृषि संसाधनों के साथ, बांग्लादेश में उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश के लिए लाभ प्रदान करता है। पूर्वोत्तर भारत से कच्चा माल मंगाना बांग्लादेश की फलों, सब्जियों और मसालों की मांग को पूरा कर सकता है। इन मूल्य श्रृंखला संपर्कों का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए व्यापार नीतियों, व्यापार सुविधा और मानकों में सुधार आवश्यक है।

व्यापार नीति (उत्पत्ति के नियमों सहित), व्यापार सुविधा, व्यापार–संबंधी मानकों और संस्थानों में सुधार दोनों देशों को मूल्य श्रृंखला संपर्कों का बेहतर लाभ उठाने में मदद कर सकते हैं।

चिकित्सा सेवाओं में व्यापार

भारत के मेडिकल टूरिज्म की दृष्टि से बांग्लादेश एक महत्त्वपूर्ण बाजार है और भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन का एक बड़ा हिस्सा होता है। बांग्लादेश के मरीज अक्सर अपने लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और कुशल चिकित्सा पेशेवरों के कारण भारत में चिकित्सा सेवा पाना चाहते हैं। भारत खुद को चिकित्सा और कल्याण संबंधी पर्यटन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए उपाय कर रहा है। इसका उद्देश्य कम उपचार लागत, विश्वस्तरीय अस्पतालों और कल्याण संबंधी सेवाओं की बढ़ती वैश्विक मांग जैसे कारकों का लाभ उठाना है। हील इन इंडिया अभियान जैसी भारत सरकार की पहल का उद्देश्य एक प्रमुख चिकित्सा पर्यटन स्थल के रूप में भारत की साख को बढ़ाना है। भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग के संभावित अवसरों में प्राथमिक देखभाल क्लीनिकों की स्थापना, कल्याण और कायाकल्प सेवाएं प्रदान करना, सीमा पार टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना एवं चिकित्सा पर्यटकों के लिए भारतीय स्वास्थ्य बीमा का विस्तार करना शामिल है। चिकित्सा पर्यटन पर एक विशिष्ट समझौते को व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) में भी शामिल किया जा सकता है।

सेवा क्षेत्र में अवसर

बांग्लादेश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सेवा क्षेत्र बड़ा योगदान दे रहा है। यह क्षेत्र विनिर्माण और अन्य उत्पादन गतिविधियों में भी बहुमूल्य योगदान दे रहा है। हालांकि सेवा क्षेत्र में व्यापार, विशेषकर निर्यात के मामले में, क्षेत्र की क्षमता की तुलना में अब भी बहुत कम है। बांग्लादेश के सेवा क्षेत्र में विकास की काफी संभावनाएं हैं। बांग्लादेश, भारत, नेपाल और भूटान को पारगमन एवं ट्रांसशिपमेंट प्रदान कर रहा है, और अंतिम बिंदु तक कनेक्टिविटी प्रदान करने वाले बेहतर पारगमन और ट्रांसपोर्टेशन संबंधी बुनियादी ढांचे से परिवहन और संचार क्षेत्र में लाभ बढ़ सकता है। इस प्रकार, गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के उत्पादन के लिए जागरूकता सृजन जैसे उपायों के माध्यम से पर्याप्त क्षमता विकसित करके, बांग्लादेश से विभिन्न सेवाओं के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। एलडीसी सेवा छूट ने बांग्लादेश और अन्य एलडीसी के लिए कुछ तरजीही बाजार पहुंच सुविधाओं का निर्माण किया है। भारत लंबे समय से पड़ोस के छात्रों के लिए एक शिक्षा केंद्र रहा है। बांग्लादेशी छात्र भारत में तीसरा सबसे बड़ा विदेशी छात्र समुदाय हैं। भारत बांग्लादेश में शिक्षा प्रणाली को उन्नत करने के लिए बांग्लादेश के साथ सहयोग कर सकता है। सेवा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा।

व्यापार संतुलन

पिछले कुछ वर्षों में, भारत और बांग्लादेश ने एकपक्षीय, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय स्तरों पर टैरिफ और गैर–टैरिफ प्रतिबंधों को समाप्त करने जैसी व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए कई पहल की हैं। इन पहलों के बावजूद, व्यापार अपेक्षित गति से नहीं बढ़ रहा है। अनुमानित सूचकांकों से पता चलता है कि भारत द्वारा बांग्लादेश को निर्यात बांग्लादेश द्वारा भारत को किए जाने वाले निर्यात की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। आपूर्ति की कमी के कारण बांग्लादेश के लिए भारतीय बाजार का लाभ उठाना मुश्किल हो गया है। बांग्लादेश को अपनी निर्यात आपूर्ति क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता है और भारत को बांग्लादेश से निर्यात बढ़ाने के लिए बाजार तक अधिकतम पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता है। टैरिफ पहलुओं के अलावा, व्यापार सुविधा के माध्यम से सीमापार आवाजाही को सुव्यवस्थित करना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए, दोनों देशों में व्यापारिक साधनों को मजबूत और आपस में जोड़कर भौगोलिक व्यापार बाधाओं को दूर करना चाहिए। भारत के साथ व्यापार विषमता को कम करने की बांग्लादेशी पक्ष की मांग दोनों देशों द्वारा सीईपीए पर हस्ताक्षर करने के साथ कुछ हद तक संभव हो सकती है। भारत के व्यापार अधिशेष का एक हिस्सा बांग्लादेश में निवेश को वित्तपोषित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। विशेष रूप से व्यापार सक्षम बुनियादी ढांचे में, जो बांग्लादेश की आपूर्ति क्षमता को बढ़ा सकता है और आने वाले वर्षों में अधिक व्यापार संतुलन की ओर ले जा सकता है। भारतीय कंपनियों द्वारा बांग्लादेश में इन निवेशों को वित्तपोषित करने के लिए एक भारत–बांग्लादेश मैत्री कोष स्थापित किया जा सकता है, जिसे भारत एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है। ■

जोखिम, बीमा और कल्याण पर निबंध

भारतीय निर्यात–आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) ने 2016 में आर्थिक शोध वार्षिक सम्मान (ब्रिक्स सम्मान) की स्थापना की। इस सम्मान का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर किसी भी विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से ब्रिक्स के पांच सदस्य देशों में से किसी भी देश के नागरिकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार, विकास और फाइनेंसिंग से संबंधित विषयों में एडवांस्ड डॉक्टरेट शोध को बढ़ावा देना है। यह लेख "जोखिम, बीमा और कल्याण पर निबंध" नामक डॉक्टरेट शोध प्रबंध पर आधारित है, जिसे इंडिया एक्ज़िम बैंक ब्रिक्स आर्थिक शोध वार्षिक सम्मान (ब्रिक्स सम्मान) 2023 के लिए विजेता प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। इसके लेखक डॉ. दिग्विजय सिंह नेगी हैं, जो वर्तमान में यूएसएस की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में फुलब्राइट–नेहरू पोस्टडॉक्टरल फेलो हैं। डॉ. नेगी ने 2018 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारत से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है।

इस अध्ययन में तीन स्वतंत्र अध्यायों का एक संग्रह शामिल है। इसमें देशों और उत्पादकों को उत्पादन के नुकसान से बचाने में अंतरराष्ट्रीय व्यापार और औपचारिक बीमा बाजारों की भूमिका का आकलन किया है। यह खाद्य वस्तुओं के समग्र उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर बढ़ती कीमतों के वितरण संबंधी प्रभावों की भी पड़ताल करता है।

हाल के वर्षों में वैश्विक खाद्य कीमतों में तेज उछाल ने वैश्विक खाद्य बाजारों के कामकाज को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं। सामान्य तौर पर, वैश्विक खाद्य उत्पादन क्षेत्रीय या राष्ट्रीय उत्पादन की तुलना में अधिक स्थिर है और इसलिए मुक्त व्यापार को कीमतों और खपत के मामले में अधिक स्थिरता प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। पहले अध्याय का मुख्य उद्देश्य जोखिम साझाकरण ढांचे में अनाज (मक्का, चावल और गेहूं) के लिए विश्व बाजारों के प्रदर्शन की पड़ताल करना है। यह अध्याय एक मानक के रूप में कुशल जोखिम–साझाकरण परिकल्पना के पूर्वानुमानों को अपनाता है। कुशल जोखिम साझा करने के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि खाद्य खपत वैश्विक उत्पादन के साथ पूरी तरह से सहसंबद्ध होनी चाहिए और घरेलू उत्पादन से स्वतंत्र होनी चाहिए। अध्याय में पाया गया है कि वैश्विक खाद्य बाजारों के लिए कुशल जोखिम–साझाकरण परिकल्पना खारिज कर दी गई है।

विकासशील देशों में कृषि और कृषि आधारित आजीविका पर मौसम की वजह से पैदा होने वाली समस्याओं का अत्यधिक खतरा रहा है। भले ही विकासशील देशों में किसान आम तौर पर गरीब हैं और भले ही वे आय के अस्थिर स्रोतों का बोझ ढोते हैं, औपचारिक बीमा उत्पादों को सीमित सफलता मिली है। किसानों के उत्पादन के इतिहास के अनुरूप पहले सर्वोत्तम बीमा कार्यक्रमों को लागू करने की कठिनाइयों ने सूचकांक आधारित बीमा उत्पादों को जन्म दिया है, जहां वर्षा, तापमान या स्थानीय औसत उपज जैसे सूचकांक से भुगतान प्रेरित होता है। प्रीमियम निर्धारित करना अपेक्षाकृत आसान है क्योंकि मौसम और औसत उपज के मानकों पर पहले का डेटा व्यक्तिगत उत्पादन इतिहास की तुलना में अधिक आसानी से उपलब्ध है। चूंकि व्यक्तिगत किसानों का भुगतान पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए बीमाकर्ता और बीमाधारक के बीच जानकारी में असमानता के कारण सूचकांक आधारित बीमा उत्पादों के विफल होने की संभावना कम होती है। विशेष रूप से, सूचकांक आधारित बीमा लेना बेकार है, खासकर जब इस पर सब्सिडी नहीं दी जाती।

अध्ययन में बताया गया है कि यील्ड हानियां और इंडेक्स हानियां छोटे विचलनों की तुलना में बड़े विचलनों के लिए अधिक होती हैं। इसका मुख्य प्रभाव यह होता है कि बीमांकिक लागत से संबंधित इंडेक्स आधारित बीमा का मूल्य (किसानों के लिए) तमाम हानियों के एवज में बीमा की तुलना में आपातकालीन हानियों (इंडेक्स की) के एवज में बीमा के लिए उच्चतम हो जाता है। अध्ययन में यह भी बताया गया है कि भारत में स्टेशन-स्तरीय वर्षा टेल-डिपेंडेंस दर्शाती है, यानी बारिश और विचलन के सह-संबंध को दर्शाती है और नौ मुख्य फसलों के लिए जिला-स्तरीय फसल पैदावार और वर्षा इंडेक्स में टेल-डिपेंडेंस दिखाई देती है अर्थात् फसल की पैदावार बारिश से संबंधित है। इसका प्रभाव यह होता है कि इंडेक्स आधारित बीमा में कम जोखिम लेने वाले किसान के लिए मूल्य, तमाम हानियों के एवज में बीमा की तुलना में आपातकालीन हानियों (इंडेक्स की) के एवज में बीमांकिक लागत के संबंध में उच्चतम हो जाता है।

दूसरे अध्याय में इस बात की पड़ताल की गई है कि भारत में वर्षा बीमा अनुबंधों को बुनियादी जोखिम को कम करने के लिए कैसे डिजाइन किया जा सकता है। अध्ययन से पता चलता है कि वर्षा के रुझान में छोटे विचलन की तुलना में बड़े विचलन के संदर्भ में उपज में होने वाली हानि और समग्र हानि के बीच संबंध अधिक मजबूत होते हैं। मुख्य निहितार्थ यह है कि (किसानों के लिए) बीमांकिक लागत की तुलना में सूचकांक–आधारित बीमा का मूल्य सभी प्रकार की हानि के लिए होने वाले बीमा की तुलना में अत्यधिक या विनाशकारी हानि (सूचकांक) के लिए होनेवाले बीमा के लिए सबसे अधिक होता है। अध्ययन से पता चलता है कि भारत में स्थानीय–स्तर की वर्षा की मात्रा अंतर–निर्भरता प्रदर्शित करती है और नौ प्रमुख फसलों के लिए जिला–स्तरीय फसल उपज और वर्षा के सूचकांक का संयुक्त वितरण भी अंतर–निर्भरता प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि जोखिम से बचने वाले किसान के लिए बीमांकिक लागत की तुलना में सूचकांक–आधारित बीमा का मूल्य सभी प्रकार की हानि के लिए होने वाली बीमा की तुलना में अत्यधिक या विनाशकारी नुकसान (सूचकांक) के लिए होने वाले बीमा के लिए सबसे अधिक होता है। विकासशील देशों में परिवार स्तर के कल्याणकारी कदमों पर उच्च खाद्य कीमतों के प्रभाव को लेकर जोरदार बहस चल रही है। चूंकि भोजन एक आवश्यक आवश्यकता है, इसलिए उच्च खाद्य कीमतों का प्रभाव चौतरफा महसूस किया जाएगा। चिंता का मुख्य कारण यह है कि चूंकि उच्च खाद्य कीमतों का जोखिम घरेलू व्यय में इसकी बजट हिस्सेदारी के समानुपाती होता है, इसलिए सबसे अधिक प्रभावित जनसंख्या समूह वे होंगे जो आय वितरण में सबसे निचले पायदान पर होंगे। इसलिए, बढ़ती खाद्य कीमतें विकासशील देशों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं, जो दुनिया के अधिकांश गरीबों का घर है।

तीसरे अध्याय में भारत में परिवार स्तर के कल्याण पर चावल और गेहूं की उच्च वैश्विक कीमतों के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। इस अध्याय में 2007–08 के वैश्विक खाद्य कीमतों के आंकड़ों में वृद्धि का उपयोग यह दिखाने के लिए किया गया है कि चावल और गेहूं की खेती करने वाले परिवारों को उच्च कीमतों से लाभ होता है। ये कल्याणकारी लाभ मुख्यतः विशुद्ध रूप से उत्पादकों को मिलते हैं। यह देखा गया है कि बाजार से खरीदे गए चावल एवं गेहूं की खपत में कमी और सरकारी सब्सिडी वाले चावल एवं गेहूं की खपत में वृद्धि से कुल उत्पादक परिवार अपने प्रति व्यक्ति खर्च और चावल व गेहूं की खपत को बनाए रखने में सक्षम थे। दूसरी ओर, समग्र उपभोक्ताओं ने चावल और गेहूं की कुल प्रतिव्यक्ति खपत में गिरावट का अनुभव किया, भले ही उन्होंने अपनी बाजार खरीद को घरेलू उपज और सब्सिडी वाले अनाज से प्रतिस्थापित कर दिया। उच्च कीमतों से परिवारों को बचाने में खाद्य हस्तांतरण की भूमिका सभी उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए स्पष्ट थीं। ■

इंडिया एक्ज़िम बैंक की ऋण–व्यवस्थाएं

सौजन्य : **ऋण–व्यवस्था समूह**

इंडिया एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है। ये ऋण-व्यवस्थाएं उन देशों के क्रेताओं को भारत से विकासपरक तथा बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं, उपकरण, माल एवं सेवाओं का आयात करने में समर्थ बनाती हैं। इंडिया एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है। इनके अंतर्गत इंडिया एक्ज़िम बैंक माल के शिपमेंट पर भारतीय निर्यातकों को कॉन्ट्रैक्ट मूल्य के 100% की प्रतिपूर्ति करता है, बशर्ते कि कुल कॉन्ट्रैक्ट मूल्य के कम से कम 75% के माल एवं सेवाओं का आयात भारत से किया गया हो। ऋण-व्यवस्थाओं के जरिए उभरते बाजारों में भारत की परियोजना निष्पादन क्षमता के प्रदर्शन में भी मदद मिली है। हाल के वर्षों में ऋण-व्यवस्थाओं ने गति पकड़ी है। विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और सीआईएस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं। ऋण-व्यवस्थाओं ने भारत के राजनीतिक, रणनीतिक और वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा देने के साथ-साथ लाभार्थी देशों में भारत की राजनीतिक ख्याति को बढ़ाने का काम भी किया है। ऋण-व्यवस्थाएं भारत की बढ़ी आर्थिक मजबूती के साथ-साथ इन ऋण-व्यवस्थाओं के प्राप्तकर्ता देशों में बुनियादी ढांचागत विकास और क्षमता निर्माण में योगदान देने की प्रतिबद्धता को वैश्विक पटल पर लाने में भी मदद करती हैं। ऋण-व्यवस्थाएं प्राप्तकर्ता देशों के ऐसे बाजारों में जरूरी माल और सेवाओं के निर्यात में भी मददगार हैं, जहां भारत की मौजूदगी न के बराबर है। भारतीय निर्यातक इंडिया एक्ज़िम बैंक से अपने माल के लिए पात्र मूल्य हासिल कर सकते हैं और इसके लिए उन पर किसी तरह का रिकोर्स नहीं रहता। बैंक द्वारा शिपिंग दस्तावेजों के निगोशिएशन/ सेवाओं के प्रावधान के एवज में किया जाता है। भारतीय निर्यातक माल के शिपमेंट पर इंडिया एक्ज़िम बैंक के जरिए पूरा भुगतान ले सकते हैं और इसमें उन्हें क्रेता या क्रेता देश से जुड़े किसी तरह के जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता।

ऋण-व्यवस्थाएं संप्रभु सरकारों को या उनकी नामित एजेंसियों को प्रदान की जाती हैं, ताकि उन देशों में क्रेता भारत से माल और सेवाओं का आस्थगित भुगतान शर्तों पर आयात कर सकें। बैंक द्वारा यथा 26 सितंबर, 2023 को अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और सीआईएस क्षेत्रों के 62 देशों को 27.98 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता के साथ 274 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं, जो भारत से निर्यातों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार ऋण-व्यवस्थाएं विकासशील देशों में भारत से परियोजनाओं, माल और सेवाओं के निर्यात के संवर्धन और सुगमीकरण के लिए प्रभावी साधन हैं।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें–

श्री दीपक कुजूर
सहायक महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात–आयात बैंक
ऑफिस ब्लॉक, टॉवर–1, 7वीं मंजिल, एड्जेसेंट रिंग रोड
किदवई नगर (पूर्व), नई दिल्ली–110023
फोन–(011) 24607700
ई–मेलः eximloc@eximbankindia.in

दास्तान–ए–कामयाबी

गयाना सरकार को भारत सरकार के सहयोग से इंडिया एक्ज़िम बैंक की 10 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार के सहयोग से यात्री–कार्गो समुद्री जहाज की खरीद के वित्तपोषण के लिए गयाना सरकार को 10 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था प्रदान की। इससे संबंधित करार पर 09 नवंबर 2016 को हस्ताक्षर किए गए।

परियोजना का विवरण

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) और गयाना सरकार के लोक निर्माण विभाग मंत्रालय के बीच करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार को 30 दिसंबर 2021 को ऋण व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया गया।

इस परियोजना में शामिल है :

a) गयाना के लिए पोत (उपकरण समेत) के डिजाइन, निर्माण, असेंबल और डिलीवरी
b) टीएंडएचडी कर्मियों को प्रशिक्षण
c) वारंटी सेवाएं और गारंटी स्लिपिंग
d) पोत के लिए स्पेयर पार्ट्स
e) जहाज मॉडल की संख्या–3

परियोजना की कुल लागत– 7.07 मिलियन यूएस डॉलर

यह परियोजना 23 अप्रैल 2023 को सफलतापूर्वक पूरी हो गई।

तिमाही गतिविधियां

सौजन्य : **कॉर्पोरेट संचार समूह**

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने गिफ्ट सिटी में अपनी सहायक कंपनी शुरू की

गुजरात इंटरनैशनल फायनैंशल टेक सिटी (गिफ्ट सिटी) में भारतीय निर्यात–आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की सहायक कंपनी इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड (एक्ज़िम फिनसर्व) का उद्घाटन 8 अगस्त 2023 को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के सचिव डॉ. विवेक जोशी ने किया।

एक्ज़िम फिनसर्व भारतीय निर्यातकों को निर्यात फैक्टरिंग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ विभिन्न व्यापार वित्त (ट्रेड फायनैंस) उत्पाद प्रदान करेगी। एक्ज़िम फिनसर्व की फैक्टरिंग सेवाओं से निर्यातकों को तीन जरूरी सेवाएं सुलभ होंगी- रिसीवेबल फायनैंसिंग, नॉन-पेमेंट के जोखिम का कवरेज और अकाउंट्स रिसीवेबल का प्रबंधन। इससे निर्यातकों के लिए नकदी प्रवाह बेहतर होगा और भुगतान जोखिम कम होगा। साथ ही, वे भरोसे के साथ नए बाजारों में कदम रख पाएंगे और अपनी वृद्धि के अवसरों को भुना पाएंगे। ये फैक्टरिंग सेवाएं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए खास तौर पर लाभकारी होंगी, क्योंकि ये सेवाएं कोलैटरल के बजाय मुख्य रूप से लेनदारी लेखों की गुणवत्ता पर आधारित होती हैं।

एक्ज़िम फिनसर्व के उद्घाटन के अवसर पर वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव, डॉ. विवेक जोशी ने कहा कि एक्ज़िम बैंक की सब्सिडियरी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वित्त की पहुंच आसान बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की दिशा में एक और बड़ा कदम है। उन्होंने उल्लेख किया कि माननीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारामन ने केंद्रीय बजट 2023 में इस सब्सिडियरी की घोषणा की थी। डॉ. जोशी ने कहा कि एक्ज़िम फिनसर्व की शुरुआत एकदम सही समय पर हो रही है और यह विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की जरूरत को देखते हुए इसकी शुरुआत का सबसे उपयुक्त समय है। उन्होंने विश्वास जताया कि एक्ज़िम फिनसर्व, फैक्टरिंग सेवाओं के लिए सुव्यवस्थित और सुगम फ्रेमवर्क का सदुपयोग करने तथा एमएसएमई निर्यातकों की जरूरतें पूरी करने वाली कंपनी साबित होगी।

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने 2023 के लिए ब्रिक्स आर्थिक शोध सम्मान विजेता की घोषणा की

डॉ. दिग्विजय सिंह नेगी को उनके डॉक्टरेट शोध प्रबंध "जोखिम, बीमा और कल्याण पर निबंध" के लिए इंडिया एक्ज़िम बैंक के ब्रिक्स आर्थिक शोध सम्मान 2023 का विजेता घोषित किया गया। केपटाउन में 22 अगस्त 2023 को डेवलपमेंट बैंक ऑफ सदर्न अफ्रीका (डीबीएसए) द्वारा आयोजित 13वें ब्रिक्स वार्षिक वित्तीय फोरम के दौरान इंडिया एक्ज़िम बैंक की प्रबंध निदेशक सुश्री हर्षा बंगारी ने डेवलपमेंट बैंक ऑफ सदर्न अफ्रीका (डीबीएसए) के अध्यक्ष प्रोफेसर मार्क स्विलिंग और डेवलपमेंट बैंक ऑफ सदर्न अफ्रीका (डीबीएसए) की सीईओ सुश्री बोइटुमेलो मोसाको की उपस्थिति में डॉ. नेगी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस फोरम में ब्रिक्स अंतर बैंक सहयोग तंत्र, यानी ब्राजील डेवलपमेंट बैंक (बीएनडीईएस); स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वीईबी आरएफ; चाइना डेवलपमेंट बैंक (सीबीडी); न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ इंडिया एक्ज़िम बैंक और डेवलपमेंट बैंक ऑफ सदर्न अफ्रीका (डीबीएसए), के सदस्य विकास बैंकों के प्रमुखों ने भागीदारी की। ■

विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति

सौजन्य: **शोध एवं विश्लेषण समूह**

अर्जेंटीना

अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था 2023 में एक विनाशकारी सूखे के कारण गहरी मंदी की ओर बढ़ रही है। इससे कृषि उत्पादन लगभग 40% तक कम होने और सकल घरेलू उत्पाद में 2.8% की कमी आने की आशंका है। भीषण सूखे और कड़े उपायों से निवेश व निजी खपत में कमी आ सकती है। इससे विकास की संभावनाएं और प्रभावित होंगी। वर्तमान में मुद्रास्फीति 2022 में औसतन 72.4% है और 2023 में खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों, निरंतर वेतन संबंधी दबाव और उच्च उपयोगिता टैरिफ के कारण 129.9% तक बढ़ने की आशंका है। सूखे के कारण "पेसो" पर दबाव बढ़ गया है। इससे अर्जेंटीना को अरबों यूएस डॉलर का नुकसान हुआ है। इस अनिश्चित वृहद् माहौल में, अनियंत्रित मैक्सी–अवमूल्यन का एक उल्लेखनीय जोखिम है। इसमें 2024 तक पीएसःयूएस डॉलर विनिमय में 819.5 तक का अवमूल्यन होने की आशंका है। अर्जेंटीना में जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान से 2023 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.8% के अनुमानित घाटे के साथ चालू खाते के प्रभावित होने की संभावना है। यह घाटा आमतौर पर चिंता का कारण नहीं बनेगा, लेकिन देश की विदेशी पूंजी तक बेहद सीमित पहुंच का मतलब है कि अनुमानित चालू खाते के घाटे के भंडार पर असर पड़ने और मुद्रा संकट के बढ़ने की आशंका है।

ईरान

पिछले एक दशक में बाहरी प्रतिबंधों और वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था काफी दबाव में रही है। इससे उसके तेल निर्यात में उल्लेखनीय संकुचन हुआ है। हालांकि, पिछले तीन वर्षों में अर्थव्यवस्था में तेजी आई है, और ईरान अपना तेल उत्पादन बढ़ाने में सफल रहा। तेल उत्पादन में वृद्धि के कारण 2023 में ईरान की अर्थव्यवस्था अनुमानित 3.0% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि निष्पादन को क्षमता से कम रखने संबंधी प्रतिबंधों के कारण अर्थव्यवस्था का संघर्ष जारी रहने की संभावना है। यहां 2022 में मुद्रास्फीति औसतन 41.2% रही और रियाल के लगातार अवमूल्यन, प्रतिबंधों से संबंधित कमी और राजकोषीय घाटे के मुद्रीकरण के कारण 2023 में मामूली रूप से बढ़कर 43% होने की उम्मीद है। प्रतिबंधों के लागू रहने के अनुमान के तहत, ईरानी रियाल (आईआर) का विनिमय 2023 में आईआरःयूएस डॉलर 505:517 (औसत) तक कम होने की उम्मीद है, जो 2022 में आईआरःयूएस डॉलर 309,691 (औसत) से अधिक है। साथ ही, उच्च मुद्रास्फीति को दर्शाता है। कमजोर नीतियां और संरचनात्मक कमियां ईरान को वैश्विक तेल और गैस बाजारों में पूंजी लगाने से रोकेंगी। उत्पादन में मौजूदा सुधार के स्थिर रहने की उम्मीद है, जिससे ईरान बाहरी मूल्य उतार–चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाएगा। उसकी निर्यात आय कम हो सकती है और 2023 में चालू खाता अधिशेष 2022 के 8.7% से घटकर 7.9% हो सकता है।

रूस

पश्चिमी प्रतिबंधों के असमान प्रभाव के कारण 2022 में 1.9% संकुचन के बाद, 2023 में रूस की आर्थिक वृद्धि में 0.5% की गिरावट आ सकती है। इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक उत्पादकता संबंधी हानि हुई और तेल व गैस, विमानन और मोटर वाहन क्षेत्रों में व्यापार अधिशेष कम हो गया है। रूसी वस्तुओं की विदेशी मांग में कमी और सैन्य गतिविधियों के कारण श्रम बल में गिरावट की वजह से कामकाजी आबादी के पलायन से भी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। हालांकि, 2024–27 की अवधि में रूस की अर्थव्यवस्था में 1.4% की वृद्धि होने की उम्मीद है। मुद्रास्फीति 2022 की 13.7% से घटकर 2023 में 6.5% रह सकती है। मुख्य रूप से 2022 से उच्च आधार प्रभावों के कारण 2024 तक इसके 5.7% तक गिरने की संभावना है। रूबल (आरबी) की विनिमय दर 2022 में औसतन आरबीःयूएस डॉलर 68.5:1 के आस-पास रही। इसके बाद, 2023 में आयात में उछाल और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण निर्यात में गिरावट की वजह से आरबीःयूएस डॉलर विनिमय में औसतन 85.5:1 तक अवमूल्यन होने की आशंका है। इसके अलावा, रूस का चालू खाता अधिशेष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.8% तक कम रह सकता है, क्योंकि तेल प्रतिबंध और मूल्य सीमा देश की विदेशी मुद्रा आय प्रभावित होती है।

इथियोपिया

इथियोपिया में 2023 में आर्थिक वृद्धि 2022 के 5.3% से बढ़कर 6% होने की उम्मीद है। नागरिक संघर्ष, उच्च मुद्रास्फीति और घटते विदेशी भंडार के प्रतिकूल अल्पकालिक प्रभाव के बावजूद, राजनीतिक माहौल में सुधार होने और 2024 की शुरुआत में आईएमएफ कार्यक्रम के शुरू होने से मध्य में परिदृश्य के अपेक्षाकृत अनुकूल होने की उम्मीद है। हालांकि, इथियोपिया खाद्य असुरक्षा की बिगड़ती स्थिति के साथ जलवायु जोखिमों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। राजकोषीय घाटे के घरेलू वित्तपोषण से जुड़ी त्वरित धन आपूर्ति वृद्धि के कारण 2023 में मुद्रास्फीति 32.8 के उच्च स्तर पर रहने की उम्मीद है। इसके 2024 में औसतन 29.6% होने की उम्मीद है और आयात निर्भरता से जुड़े मुद्रा अवमूल्यन के कारण दहाई अंकों का रुझान जारी रह सकता है। वर्ष 2022 में स्थानीय मुद्रा "बीर" की विनिमय दर यूएस डॉलर के मुकाबले औसतन 52.01:1 के रही। यह 2023 में 57:1 (बीरःयूएस डॉलर) के आसपास रह सकती है। संभावना है कि सरकार मुद्रा के मामूली अवमूल्यन की अनुमति दे सकती है क्योंकि उच्च मुद्रास्फीति का दबाव नीतिगत प्रयासों को कमजोर कर रहा है। हालांकि आईएमएफ कार्यक्रम के तहत बेहतर बाहरी संतुलन से मुद्रा को कुछ सहायता मिलनी चाहिए। चालू खाते का घाटा 2022 में जीडीपी के 4.4% से घटकर 2023 में जीडीपी के 3.9% तक पहुंच सकता है। व्यापार रुझानों के बाद 2024 में जीडीपी 4.3% तक बढ़ सकती है। ■

मुद्राओं की स्थिति

सौजन्यः **ट्रेजरी और लेखा समूह**

रूसी रूबल

Rb

रूबल रूसी संघ की मुद्रा है। इसका उपयोग रूस के साथ–साथ रूसी सैन्य कब्जे वाले यूक्रेन के हिस्सों और जॉर्जिया के रूसी कब्जे वाले हिस्सों में भी किया जाता है।

देश का व्यापार अधिशेष, जो परंपरागत रूप से अपनी मुद्रा का समर्थन करता है, कम हो गया है। इससे पहले, तेल की ऊंची कीमतों और आयात में कमी के कारण रूस ने पर्याप्त व्यापार अधिशेष बनाए रखा। हालांकि, तेल की कीमतों में गिरावट आई है, और कच्चे तेल और डीजल जैसे तेल उत्पादों पर मूल्य नियंत्रण सहित पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस की तेल विक्रय क्षमता को पेचीदा बना दिया है। निर्यात में कमी के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा का कम प्रवाह रूबल के अवमूल्यन का प्रमुख कारक है। हालांकि, रूसी अर्थव्यवस्था सरकारी खर्च और अन्य देशों के साथ अपने व्यापार की मदद से उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है।

रूबल का यह अवमूल्यन, हालांकि तेल और गैस की कमाई से सरकारी खर्च रूबल के रूप में बढ़ा जो मास्को के लिए फायदेमंद रहा, फिर भी बहुत अधिक हो गया। इससे केंद्रीय बैंक को हस्तक्षेप करना पड़ा। जून के बाद से, यूक्रेन के साथ संघर्ष के शुरुआती चरण के बाद यूएस डॉलर के मुकाबले रूबल के सबसे निचले स्तर 150 तक गिरने की प्रतिक्रिया के रूप में केंद्रीय बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दर को 4.5% अंक से बढ़ाकर 13% तक कर दिया। रूसी सेंट्रल बैंक का लक्ष्य आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी, विशेष रूप से तेल और प्राकृतिक गैस के कारण होने वाली मुद्रास्फीति से निपटना है, क्योंकि रक्षा खर्च बढ़ता है और प्रतिबंधों का असर आंशिक रूप से दरों में वृद्धि के माध्यम से होता है।

रूबल 29 सितंबर 2023 को प्रति यूएस डॉलर 97.00 पर बंद हुआ।

यूरो

€

यूरो यूरोपीय संघ के 20 देशों की मुद्रा और मौद्रिक इकाई है। यूरो को पहली बार 1999 में एक गैर–नगद मौद्रिक इकाई के रूप में लॉन्च किया गया था, और 2002 में मुद्रा सिक्के और नोट जारी किए गए। हाल ही में, क्रोएशिया ने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया।

यूरोपीय आयोग ने पूर्वानुमान लगाया कि जर्मनी की धीमी वृद्धि यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को धीमा कर देगी। वृद्धि में गिरावट का मुख्य कारण उच्च मुद्रास्फीति और जर्मनी की आर्थिक स्थिति होगी। इस साल जर्मनी के मंदी की चपेट में आने की आशंका है।

जर्मनी (5.9%) और स्पेन (2.6%) में उच्च मुद्रास्फीति ने दर में वृद्धि की संभावना बढ़ा दी। परिणामस्वरूप, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने सितंबर की नीति में दरों को 4.5% के रिकॉर्ड तक बढ़ा दिया और 2024 के लिए अपने मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को अपडेट किया। फिर भी यूरो में गिरावट आई। इस महीने डॉलर के मुकाबले लगभग 2% की गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरह ईसीबी ने भी दरों को लंबे समय तक अधिक रहने के विचार को आगे बढ़ाया। इस पृष्ठभूमि को मुद्रा का समर्थन करना चाहिए लेकिन यूरो के संदर्भ में, व्यापारियों को इस क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर प्रदर्शन की उम्मीद है। उनका दावा है कि ईसीबी को फेड से पहले कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्षेत्र का आर्थिक प्रदर्शन कमजोर रहने की भी आशंका है।

29 सितंबर 2023 को यूएस डॉलर के मुकाबले यूरो 1.0570 पर बंद हुआ।

तुर्की लीरा

TL

तुर्की लीरा तुर्की में वैध मुद्रा है। एक ऐसी मुद्रा, जिसने अपने पूरे इतिहास में कई अवमूल्यन प्रक्रियाओं का सामना किया है। इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 1995 और 1996 के बीच तथा 1999 से 2004 तक दो मौकों के दौरान दुनिया की सबसे कम मूल्यवान मुद्रा के रूप में वर्गीकृत किया गया।

तुर्की की वार्षिक मुद्रास्फीति पिछले साल अक्टूबर में 85.51% तक पहुंच गई, जो जून 1998 के बाद सबसे अधिक है। केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती की एक श्रृंखला के बाद तुर्की लीरा में महत्त्वपूर्ण अवमूल्यन के बाद मुद्रास्फीति में वृद्धि देखी गई। बढ़ती कीमतों के बावजूद, केंद्रीय बैंक ने अपने सहजता चक्र को जारी रखा। हाल ही में अक्टूबर 2022 की पॉलिसी मीटिंग में नीतिगत दर को घटाकर 10.50% कर दिया।

वित्तीय वर्ष 2022 में डॉलर की तुलना में लीरा का मूल्य लगभग 81% और वित्तीय वर्ष 2023 में अतिरिक्त 30% अवमूल्यन हुआ है। इसके अलावा, जबकि तुर्की के केंद्रीय बैंक ने वर्ष के अंत में मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान बढ़ाकर 65.20% कर दिया, सरकार का आर्थिक कार्यक्रम उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कम दरों को प्राथमिकता देता है।

हाल ही में, केंद्रीय बैंक ने जून, जुलाई और अगस्त की पॉलिसी मीटिंग में अपनी प्रमुख दर को 8.50% से बढ़ाकर 25% कर दिया, जो मौद्रिक सहजता के वर्षों में बदलाव का प्रतीक है। परिणामस्वरूप, लीरा लगभग 42% कमजोर हो गई। यह यूएस डॉलर के मुकाबले 27.2994 के नवीनतम रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई।

29 सितंबर 2023 को यूएस डॉलर के मुकाबले लीरा 27.3712 पर बंद हुई।

चीनी युआन

Rmb

चीनी युआन इस साल सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली एशियाई मुद्राओं में से एक है। चीन बड़ी मात्रा में पूंजी के बहिर्वाह (आउटफ्लो) का सामना कर रहा है। इससे अधिकारियों के बीच चिंता बढ़ गई है क्योंकि युआन के अवमूल्यन पर दबाव बढ़ रहा है। युआन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें सुस्त अर्थव्यवस्था, चीन के विकल्प में जुटी वैश्विक कंपनियां और सेवा व्यापार को प्रभावित करने वाली विदेशी यात्रा में पुनरुत्थान शामिल है। विदेशी निवेशकों ने चीनी सॉवरेन बॉन्ड में हिस्सेदारी कम कर दी है। इसके अतिरिक्त, चीन द्वारा कोविड–19 प्रतिबंधों को हटाने के बाद भी, विदेशी पर्यटकों की कमी के कारण सेवा व्यापार में घाटा बना हुआ है।

आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि अगस्त में पूंजी खाते से 49 बिलियन यूएस डॉलर का आउटफ्लो हुआ। यह दिसंबर 2015 के बाद सर्वाधिक है। यह पूंजी पलायन चीन की आर्थिक मंदी और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ब्याज दर के बढ़ते अंतर के कारण हुआ। इससे स्थानीय मुद्रा "युआन" की गिरावट सितंबर 2023 में यूएस डॉलर की तुलना में 7.3498 के 16 साल के निचले स्तर पर आ गई। यह कमजोरी चीनी बाजारों के आकर्षण को और कम कर सकती है। आउटफ्लो तेज कर सकती है, जो वित्तीय बाजारों को अस्थिर कर सकती है।

28 सितंबर 2023 को यूएस डॉलर की तुलना में युआन 7.3010 पर बंद हुआ। ■

एक्ज़िम मित्र

सौजन्य: **एक्ज़िम मित्र समूह**

भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने और भारतीय उद्यमियों के बीच व्यापार वित्त, ऋण बीमा और व्यापार से जुड़ी अन्य जानकारियों के प्रसार की विषमता को दूर करने के लिए इंडिया एक्ज़िम बैंक ने एक पोर्टल तैयार किया है। इसके मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं। निर्यात के लिए ऋण उपलब्धता के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना और व्यापार से संबंधित सूचनाएं प्रदान करना। एक्ज़िम मित्र के जरिए ऐसे प्रयास करना, जिनसे भारतीय उद्यमियों की अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी जिज्ञासाओं का समाधान हो। इनमें से कुछ को नीचे दिया गया हैं:

निर्यात व्यवसाय में भुगतान के सुरक्षित तरीकों के बारे में जानकारी

भुगतान पाने के लिए आयातक को निर्यातक की प्रतिबद्धता के वर्तमान/पिछले ट्रैक, क्रेडिट पात्रता, बाजार रिपोर्ट, माल की गुणवत्ता, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रिपोर्ट आदि पर ध्यान देना चाहिए।

सबसे अधिक सुरक्षित से सबसे कम सुरक्षित भुगतान के तरीके इस प्रकार हैं :

1. भुगतान खाता खोलें (आयातक के लिए सबसे अधिक सुरक्षित)
2. विनियम पत्रों की वसूली (डीए)
3. स्वीकारने पर देय प्रलेख (डीपी)
4. आयात साख पत्र
5. अग्रिम भुगतान (आयातक के लिए कम सुरक्षित)

इसके अलावा कोई भी अपनी आवश्यकता के अनुसार एक्ज़िम मित्र पोर्टल के अलग–अलग सेक्शन देख सकता है।

भारत से ऑस्ट्रेलिया तक ताजा अनार के निर्यात के लिए कस्टम नियमों, प्रक्रियाओं और दस्तावेजों के बारे में जानकारी

भारत से ऑस्ट्रेलिया में ताजा अनार के निर्यात के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार के कृषि विभाग द्वारा निर्धारित आयात शर्तों का अनुपालन आवश्यक है। इन शर्तों में अनार (पुनिका ग्रैनटम) और भारत से प्राप्त खाने के लिए अनार के दाने दोनों शामिल हैं। इन उत्पादों के लिए आयात शर्तों के बारे में अधिक जानकारी बायोसिक्योरिटी इम्पोर्ट कंडीशंस सिस्टम (बीआईसीओएन) के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

जैसा कि ऑस्टेलियाई कृषि विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है, सभी आयातित अनार भारत में मान्यता प्राप्त वाणिज्यक उत्पादन क्षेत्रों से होने चाहिए। खासकर, ऑस्ट्रेलिया ने भारत से अनार के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए बाजार पहुंच का विस्तार किया है। दोनों देशों के बीच आपसी सहमति बनी और जून 2020 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार के कृषि, जल और पर्यावरण विभाग (डीएडब्ल्यूई) द्वारा एक कार्य योजना दस्तावेज जारी किया गया। यह दस्तावेज भारत से ऑस्ट्रेलिया को ताजा अनार के निर्यात के लिए अपेक्षित मानदंड और अनुपालन उपायों को दर्शाता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया दिए गए लिंक को देखें।

https://www.apeda.gov.in/apedawebsite/Announcements/ADVISORY_14.09.2020.pdf

बैक–टू–बैक लैटर ऑफ क्रेडिट (साख पत्र) क्या है? यह किसी निर्यातक को अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में कैसे मदद करता है?

बैक–टू–बैक लैटर ऑफ क्रेडिट जिन्हें अक्सर बीटीबी एलसी के रूप में जाना जाता है, एक महत्त्वपूर्ण वित्तीय साधन के रूप में उभरा है। यह सहज और अधिक सुरक्षित सीमा पार आदान–प्रदान का मार्ग प्रशस्त करता है। जोखिमों को कम करने, जटिल लेन-देन को सुविधाजनक बनाने, गोपनीयता बनाए रखने, नियामक मतभेदों को दूर करने और विश्वास बढ़ाने की इनकी क्षमता इन्हें व्यापार में आवश्यक बनाती है। इसमें विभिन्न बैंकों द्वारा जारी किए गए दो अलग–अलग लैटर ऑफ क्रेडिट शामिल होते हैं। पहला- लैटर ऑफ क्रेडिट जो मास्टर एलसी के रूप में जाना जाता है, खरीदार के बैंक द्वारा विक्रेता (निर्यातक) के पक्ष में खोला जाता है। इसके साथ ही, विक्रेता अपने देश के स्थानीय बैंक से द्वितीय लैटर ऑफ क्रेडिट, जिसे सब–एलसी कहा जाता है, को सुरक्षित करने के लिए गारंटी के रूप में मास्टर एलसी का उपयोग करता है।

सरल शब्दों में, मान लें कि कंपनी XYZ एक आभूषण विक्रेता है। इसके खरीदारों में से एक, कोई छोटा डिपार्टमेंटल स्टोर, कंपनी XYZ को एक लैटर ऑफ क्रेडिट देता है। ताकि कंपनी XYZ को आश्वस्त किया जा सके कि वह उसके द्वारा दिए गए बड़े आभूषण ऑर्डर का भुगतान कर सकता है। बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए, कंपनी XYZ को अपने किसी आपूर्तिकर्ता से बड़ी मात्रा में कच्चा माल खरीदना होगा। कंपनी ने डिपार्टमेंट स्टोर को लैटर ऑफ क्रेडिट के लिए धन्यवाद दिया। कंपनी XYZ जानती है कि उसे भुगतान मिलेगा और इस प्रकार वह भुगतान के आश्वासन के लिए आपूर्तिकर्ता को उस लैटर ऑफ क्रेडिट का उपयोग कर सकता है।

लैटर ऑफ क्रेडिट को लेकर बिल छूट के लिए पात्रता मानदंड क्या है? क्या निर्यात संबंधी औपचारिकताएं पूरी हो जाने और निर्यात संबंधी सभी दस्तावेज बैंक में जमा हो जाने के बाद किसी को बिल में छूट के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है?

अगर लैटर ऑफ क्रेडिट पर रोक होगी तो करार पर भी रोक होगी। कोई भी एक्ज़िम मित्र पोर्टल के व्यापार वित्त सेक्शन पर विजिट कर सकता है, जहां चुनिंदा बैंकों के लैटर ऑफ क्रेडिट यानी संबंधित उत्पाद (विभिन्न उत्पादों के बीच) व्यापक नियमों और शर्तों के साथ सूचीबद्ध किए गए हैं।

सुरक्षा की आवश्यकता के संबंध में, यह बैंक की नीति पर निर्भर करता है। कभी–कभी, लैटर ऑफ क्रेडिट का लाभार्थी लैटर ऑफ क्रेडिट जारी करने वाले बैंक से ही बिलों में छूट चाहता है। ऐसे मामलों में, बैंक लाभार्थी को जारी बिलों पर तभी छूट दे सकते हैं, जब बैंक ने लाभार्थी को रेगुलर फंड–आधारित ऋण सुविधाएं स्वीकृत की हों। यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि लाभार्थी का बैंक उसके खाते में नगदी प्रवाह से वंचित न हो, लाभार्थी को उस बैंक के माध्यम से बिलों पर छूट को लेकर करार करना चाहिए, जिसके साथ वह स्वीकृत ऋण सुविधाओं का लाभ ले रहा है।

आंकड़ों में भारतीय अर्थव्यवस्था

सौजन्यः **शोध एवं विश्लेषण समूह**

वस्तु व्यापार

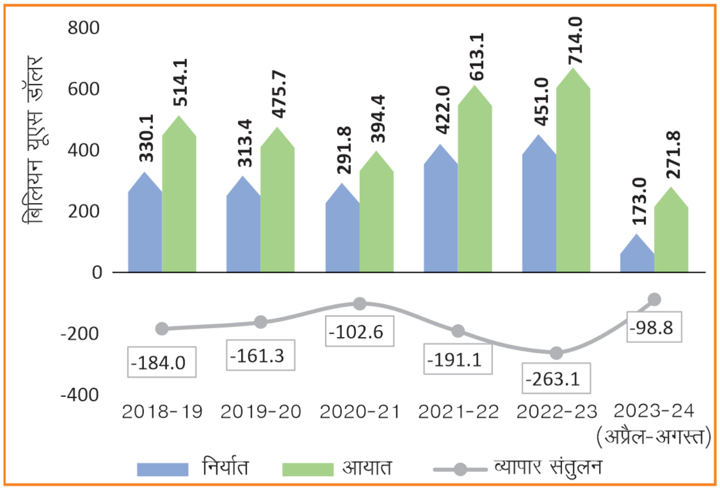

स्रोतः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

सेवाएं व्यापार

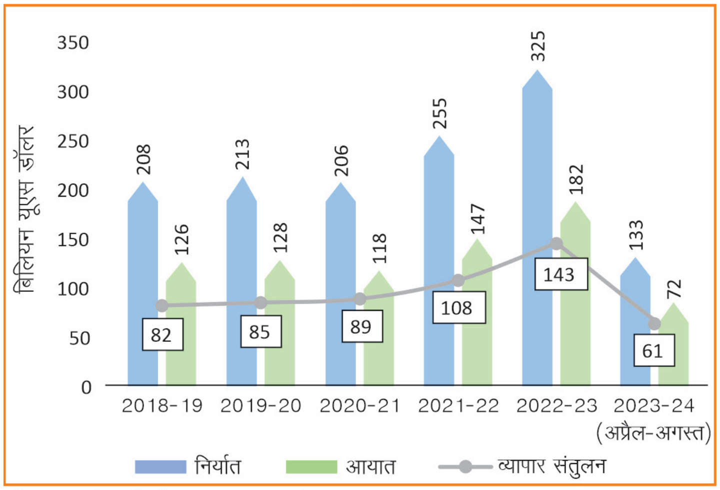

स्रोतः आरबीआई और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

चालू खाता घाटा

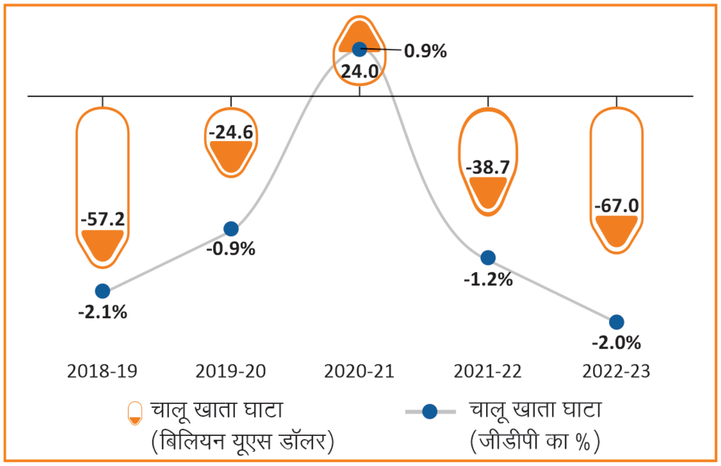

स्रोतः आरबीआई

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)

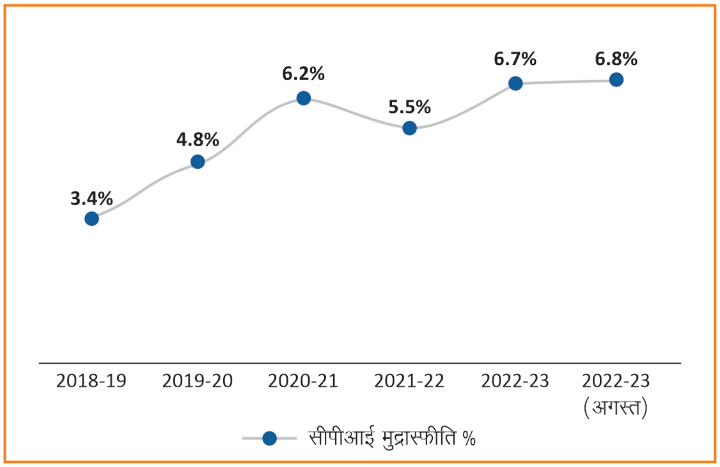

स्रोतः सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा निवेश का प्रवाह

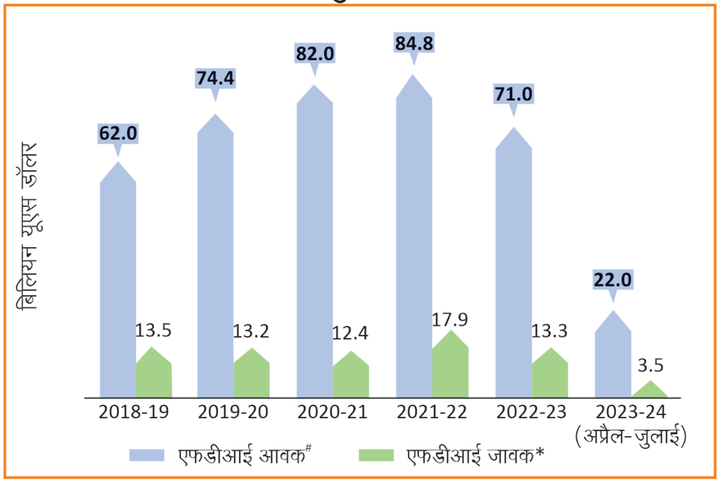

*नोट: *एफडीआई जावक वास्तविक आंकड़े दर्शाते हैं और इसमें इक्विटी, ऋण, इन्वोक की गारंटियां शामिल हैं।*

#एफडीआई आवक में इक्विटी, पुनर्निवेश आय और अन्य पूंजी शामिल है।

स्रोतः आरबीआई और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

क्षेत्रवार उत्पादन

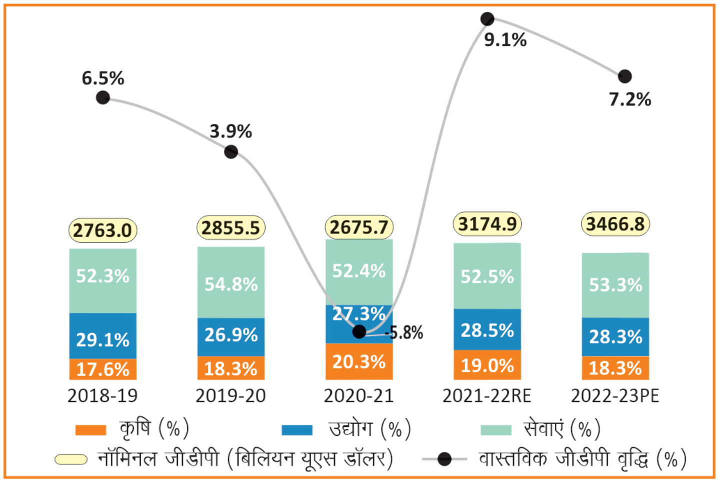

नोटः पीले रंग के आंकड़े नॉमिनल जीडीपी (बिलियन यूएस डॉलर) को दर्शाते है ;

आरई– संशोधित अनुमान ; पीई– अंतिम अनुमान

स्रोतः अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार